साप्ताहिक
शांति मिशन
नई दिल्ली

वर्ष-29 अंक- 14 03 - 09 अप्रैल 2022 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

महिलाओं के खिलाफ़ अपराध
साझा दर्द, साझी उम्मीदें
पृष्ठ-6

उपभोक्ता के हित और क़ानून
पृष्ठ-7

भारत का चुनावी सर्कस

क्या कोई एक राष्ट्र, एक चुनाव मानेगा?

1999 में एक लोकसभा कमेटी ने सिफारिश की थी कि रोज़-रोज़ के चुनावी मोड से बचने और ख़र्चे कम करने के लिए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराएं जाएं, मगर इस मामले में आज तक राजनैतिक दलों में सहमति ही नहीं बन पाई है।

05 राज्यों में विधानसभा चुनावों की जीत का बिगुल बंद भी नहीं हुआ था कि पार्टियों ने दिसंबर में 'ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल सर्कस' के अगले दौर के लिए तैयारियां शुरू कर दीं, जिसमें मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सभी जाति, रंग, पंथ के राजनेता अनेक प्रयास करेंगें और वोट बैंक की राजनीति करेंगे। निरंतर चुनावों के क्रम में प्रशासन की कोई परवाह नहीं करता, जिसके चलते यह एक पुरानी बीमारी बन गई है।

साल 2019 के लोकसभा चुनावों से लेकर अब तक देश में 24 विधानसभाओं के लिए चुनाव हो चुके हैं और इस वर्ष के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के लिए चुनाव होंगे। फिर अगले वर्ष फरवरी में नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय, मई में कर्नाटक, नवम्बर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, दिसंबर में राजस्थान और तेलंगाना, अप्रैल 2024 में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, अक्तूबर 2024 में महाराष्ट्र, हरियाणा, नवंबर दिसंबर में झारखंड विधानसभाओं के चुनाव होंगे। उसके बाद फरवरी 2025 में दिल्ली और नवंबर-दिसंबर 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे। देश पूरे वर्ष निरंतर चुनावी मोड से ग्रस्त रहता है जो हमारी शासन व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है इसलिए समय आ गया है कि हमारी राजनीतिक पार्टियां संसद, राज्य विधानसभाओं से लेकर पंचायत तक एक राष्ट्र, एक चुनाव के विचार को कार्यान्वित करें। वस्तुत: प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2016 में यह विचार दिया था। इससे न केवल राजकोष और पार्टियों का पैसा बचेगा, अपितु केन्द्र और राज्यों में सरकारों को सुशासन पर ध्यान केन्द्रित करने में सक्षम बनाएगा, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के चलते प्रशासन एक तरह से ठप्प सा हो जाता है।

वर्ष 1999 में विधि आयोग और कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं ताकि मतदाता एक ही दिन के दोनों के लिए मतदान कर सकें। ज़रा सोचिए। प्रत्येक वर्ष में एक बड़ा चुनाव हो, जिसमें एक जैसा मतदाता सूचि हो। इससे न केवल समय बचेगा अपितु सरकार और विभिन्न हितधारकों का व्यय भी बचेगा। सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को लंबे समय तक चुनावी डयूटी से मुक्त रखा जा सकेगा।

अनेक अच्छी पहलें चुनावों को ध्यान में रखते हुए छोड़ दी जाती हैं कि कहीं इससे जाति, समुदाय, धर्म या क्षेत्रीय वोट बैंक गड़बड़ा न जाए। बार-बार चुनाव होने से संकीर्ण लोकप्रिय और राजनीतिक दृष्टि से सुरक्षित उपाए किए जाते हैं और कठिन ढांचागत सुधारों को छोड़ दिया जाता है, जबकि दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में ऐसे कठिन ढांचागत सुझाव जनता के लिए अधिक लाभप्रद होते हैं।

आपको याद होगा कि वर्ष 1951 से 1967 तक लोकसभा और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराए गए थे और यह चक्र तक टूटा जब 1968 और 1969 में कुछ राज्य विधानसभाओं को समय पूर्व भंग कर दिया गया। 1970 में चौथी लोकसभा को समय पूर्व भंग कर दिया गया और 1971 में चौथी लोकसभा के लिए चुनाव हुए, जिसके चलते केन्द्र और राज्यों में लोकसभा और विधानसभाओं के समय पूर्व विघटन के कारण अनेक अस्थिर सरकारें बनीं। यह सच है कि केन्द्र और राज्यों में चुनावी मुद्दे अलग-अलग हैं और उन मुद्दों को मिलाना ठीक नहीं। इससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है क्योंकि किसी पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों और कार्यकरण के चलते वह राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन की हक़दार है, किन्तु राज्य में उसके ख़राब प्रदर्शन के चलते वह दंड की भागीदार भी होती है।

लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराने के राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के एक साथ चुनाव कराने से मतदाता सामान्यत: एक ही पार्टी को वोट देते हैं। इसके अलावा यदि कोई जनादेश प्राप्त सरकार को लोकसभा या राज्यविधान सभा में सत्ताच्युत कर दिया जाता है तो क्या वह सत्ता में बनी रहेगी या उसके स्थान पर दूसरी सरकार बनेगी, जिसे आवश्यक नहीं कि लोकप्रिय जनादेश प्राप्त हो। कुल मिलाकर जिस सरकार का जनादेश प्राप्त न हो वह लोगों पर थोपी जा सकती है और इस तरह से इसमें राजशाही और निरंकुशशाही की बू आती हैं तथा एक तरह से अप्रितिनिधक सरकार बन जाती है। तथापि कुछ लोगों का मानना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं और उनका एक निर्धारित कार्यकाल नियत किया जा सकता है। यदि कोई निर्वाचित सरकार गिर जाती है तो जब तक नए चुनाव नहीं होते केन्द्र उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है किन्तु केन्द्र में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान नहीं है। इससे अनेक समस्याएं पैदा होंगी।

कुछ संविधान विशेषज्ञों ने इस समस्या का समाधान सुझाया है। यदि लोकसभा का शेष कार्यकाल लंबा न हो तो राष्ट्रपति द्वारा देश का शासन चलाने का प्रावधान किया जा सकता है, जो अगले सदन के गठन तक उसके द्वारा नियुक्त मंत्रि परिषद की सलाह पर कार्य करेगा और यदि लोकसभा का शेष कार्यकाल लंबा हो तो फिर चुनाव कराए जा सकते हैं और ऐसी स्थिति में सदन का कार्यकाल उसकी मूल अवधि में से शेष अवधि के लिए हो। तथापि इस विचार पर गहनता से बहस किए जाने की आवश्यकता है। फिर इस समस्या का समाधान क्या है? वर्ष 2015 में विधि संबंधी स्थायी संसदीय समिति ने लोकसभा और अन्य राज्य विधान सभाओं के एक साथ चुनाव कराने की एक व्यावहारिक विधि की सिफारिश की थी। वर्ष 2018 में

बेल्जियम में संघीय संसद के चुनाव प्रत्येक 05 वर्ष में यूरोपीय संसद के चुनाव के साथ होते हैं। इसी तरह की प्रणाली स्पेन, हंगरी, पोलैंड, स्लोवेनिया, अल्बानिया, इस्राईल, लेसोथो, फिलीपींस, कोस्टारिका, बोलीविया, ग्वाटेमाला में भी है और पिछले वर्ष इंडोनेशिया ने भी इसी प्रणाली को अपनाया है। हम अमरीकी मॉडल को भी अपना सकते हैं जहां पर राष्ट्रपति और राज्यों के गवर्नरों का चुनाव 04 वर्ष की निर्धारित अवधि के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है और वे अपनी टीम का चयन करते हैं। राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा और सीनेट के प्रति उत्तरदायी होता है किन्तु उन्हें उनका विश्वास मत नहीं लेना होता है। इससे सुशासन, स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित होती है, जिससे वह सत्ता खोने के डर के बिना कठिन निर्णय ले पाता है। समय आ गया है कि भारत में निरंतर चुनाव सिंड्रोम को समाप्त करने के लिए बदलाव किया जाए, यह वक़्त का तक़ाज़ा भी है।

बाक़ी पेज 11 पर

पाकिस्तान

भारत के क़सीदे क्यों पढ़ रहे हैं इमरान ख़ान

इमरान ख़ान को अब समझ में आया। जब उनकी सत्ता का संध्याकाल आने को है तब आंखें खुलीं। मलकान रैली में वे भारतीय विदेश नीति पर लट्टू दिखाई दिए। पाक के प्रधानमंत्री ने माना कि हिन्दुस्तान की स्वतंत्र विदेश नीति शानदार है। वह एक तरफ क्वाड में अमेरिका का साथी है, तो दूसरी ओर रूस का भरोसेमंद रणनीतिकार साझीदार है। अमेरिका की बंदिशों के बाद भी वह धड़ल्ले से रूस का तेल खरीद रहा है। वे दोहराते हें कि इंडिया की विदेश नीति उसके अपने लोगों की भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है (यहां हम भारत की विदेश नीति के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं)

हालांकि यहां एक प्रश्न इमरान ख़ान से भी बनता है कि क्या उनके इस कथन में कोई मजबूरी छिपी है? उन्हें अपने देश की स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करने से कौन रोक रहा है। क्यों वे अपने नागरिकों की भलाई करने वाली विदेश नीति आज तक नहीं बना सके। जहां तक क्वाड की बात है तो एक बार फिर इमरान ख़ान के अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान की पोल खुल गई है। क्वाड का गठन आपदा राहत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति के मक़सद से किया गया था। चीन के इरादों पर नज़र रखना भी से मुक़ाबला करने की बात इन देशों के संगठन में नहीं है और न ही एक दूसरे के कारोबारी हितों में दख़ल देने की मंशा है। तो फिर इमरान ख़ान ने भारत के कसीदे क्यों पढ़े। इसका उत्तर मैं अपने नज़रिये से देना चाहूंगा।

इमरान ख़ान नियाज़ फौज के कठपुतली प्रधानमंत्री हैं। इमरान की पार्टी सेना की मेहरबानी से हुकूमत में आई थी। सेना ने अनेक धांधलियां कर उन्हें प्रधानमंत्री बनवाया था। उस समय उनका सियासी क़द नटा था और वे वैचारिक रूप से दुर्बल थे। जब तक रीढ़विहीन निर्बल इमरान ख़ान सियासी में सैनिक बैसाखियों पर जीवित रहा उसने हक़ीक़त से आंखें मूंद कर रखीं। न उसे अवाम के हित दिखाई दिए और न राष्ट्र के। अब ख़बरें मिल रहीं हैं कि फौज ने पद छोड़ने के लिए कह दिया है तो इमरान ख़ान की संवेदनाओं के सारे बिन्दु जाग उठे हैं। विपक्ष के नाक में दम कर दिया है। उसका अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री की घबराहट का सबब है, क्योंकि समर्थन दे रहे सांसद ही उनसे किनारा करने लगे हैं। उनकी सरकार के पास केवल 07 सांसद बहुमत के बिन्दु 172 से अतिरिक्त हैं।

इनमें से 24 सांसद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की यानि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मेहमानी का आनंद ले रहे है। वे मीडिया के सामने ऐलान कर चुके हैं कि इमरान ख़ान को उनका समर्थन अब नहीं है। इसके अलावा प्रतिपक्षी मोर्चे के संयोजक मौलाना रहमान का दावा है कि पांच सांसद उनके साथ आ चुके हैं। यानि इमरान ख़ान की पार्टी अल्पमत में आ गई है। इस तरह तकनीकी तौर पर अविश्वास प्रस्ताव की भी ज़रूरत नहीं रही। ऐसे में इमरान को डर है कि यदि विपक्ष ने सत्ता में आने पर उनके भ्रष्टाचार के मुक़दमों की फाइल खोल दी और उन्हें नवाज़ शरीफ की तरह देश छोड़ भागना पड़ा तो कौन उन्हें शरण देगा? इमरान ऊटपटांग बयानों से अमेरिका और पश्चिमी देशों को नाराज़ कर चुके हैं, यूरोप के देशों पर प्रश्न उठा चुके हैं। मौजूदा स्थितियों में रूस और चीन उन्हें शरण देने की सोचेंगे भी नहीं।

वैसे भी चीन के राष्ट्रपति पुरानी बातें नहीं भूलते। शी जिनपिंग को याद होगा कि इमरान ख़ान एक बार उनकी पाकिस्तान यात्रा के विरोध में धरने पर बैठ गए थे। शी जिनपिंग को इस कारण यात्रा रद्द करनी पड़ी थी। ले-देकर हिन्दुस्तान ही बचता है। शायद यहां उन्हें शरण मिल जाएं। इसलिए वे अपने भाषण में विरोधाभासी बिन्दुओं के बीच संतुलन खोजने के लिए भारत की तारीफ करते हैं। एक दो बार पहले भी वे भारत की प्रशंसा कर चुके हैं। कहा जाता है कि भारत में उन्होंने कुछ गुप्त निवेश भी किया है। कहावत सही है कि जब इंसान बेहद अकेला होता है अथवा उसका अंत समय आता है तो उसके सारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। उसे ज़िन्दगी का सच पता चल जाता है। यदि इस सच का अहसास पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कुर्सी संभालते ही कर लेते तो संभवतया अब तक कश्मीर समेत दोनों मुल्कों के बीच सारी समस्याओं का समाधान भी खोज लेते। लेकिन इस पड़ोसी मुल्क के हर वज़ीरे आज़म का हाल ऐसा ही रहा है। मन ही मन उसे भारत से बेहतर

बाक़ी पेज 11 पर

तीनों निगम के एक होने के बाद 220 तक सिमट जाएगी वार्डों की संख्या

गृह मंत्रालय के एमसीडी के यूनिफिकेशन प्रपोजल पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। अब यूनिफिकेशन की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। इसके पहले मंत्रालय ने तीनों एमसीडी को एक करने को लेकर दिल्ली में वार्डों के परिसीमन को लेकर एमसीडी अफसरों से सुझाव मांगें थे। अफसरों ने मंत्रालय को जो सुझाव दिया है, उसमें दिल्ली की मौजूदा जनसंख्या के आधार पर परिसीमन कराने की बात कही है। नई परिसीमन के आधार पर वार्डों की संख्या करीब 50-52 तक कम करने का भी सुझाव दिया है।

वर्तमान में तीनों एमसीडी को मिलाकर 272 वार्ड हैं। नॉर्थ एमसीडी के 06 जोन में 104, साउथ एमसीडी के 04 जोन में 104 और ईस्ट एमसीडी के दो जोन में 64 वार्ड हैं। परिसीमन के बाद वार्डों के बंटवारे का जो प्लान तैयार किया गया है, उसमें साउथ और ईस्ट एमसीडी में वार्डों की संख्या कम की जाएगी। ऐसा इसलिए कि साउथ एमसीडी में 04 जोन हैं और वार्ड 104 हैं। इसी तरह से ईस्ट एमसीडी में भी वार्डों की संख्या अधिक है, जिसे कम किया जाएगा। तीनों एमसीडी के अलग-अलग विधानसभाओं में से कई में 04 वार्ड के बजाय 7 या 8 वार्ड हैं, जिसे कम किया जाएगा।

एक वार्ड में अधिकतम 80 हजार तक वोटर्स होंगे

2007 में जब परिसीमन किया गया था, तब एक वार्ड में अधिकतम वोटर्स की संख्या 40 हज़ार रखी गई थी। 2016-17 में परिसीमन के दौरान एक वॉर्ड में वोटरों की संख्या 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार कर दिया गया। अब, जो परिसीमन का प्लान है, उसमें वार्डों की संख्या कम की जाएगी और वोटरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। एक वार्ड में अधिकतम 80 हजार तक वोटर्स होंगे। सूत्रों का कहना है कि मौजूदा परिसीमन के आधार पर एमसीडी के कार्य क्षेत्र में आने वाले 68 विधानसभाओं में से प्रत्येक 4-4 ही वॉर्ड होने चाहिए। कई ऐसी विधानसभा हैं, जिसमें वार्डों की संख्या काफी अधिक है। साउथ एमसीडी के विकासपुरी विधानसभा में 04 के बजाय 7 वार्ड हैं। बदरपुर विधानसभा में 6 और ओखला में 5 वार्ड हैं। मटियाला विधानसभा में भी 7 वार्ड हैं। नार्थ एमसीडी में बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में 6 वार्ड हैं। नरेला, रिठाला, मुंडका और किराड़ी विधानसभा क्षेत्रों में 5-5 वार्ड हैं। नॉर्थ एमसीडी में कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र भी है, जहां सिर्फ 3-3 वार्ड ही हैं। इनमें आदर्श नगर, त्रिनगर, वजीरपुर, मॉडल टाउन, चांदनी चौक, बल्लीमारान और करोल बाग विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इसलिए प्लान है कि यूनिफिकेशन से पहले मौजूदा जनसंख्या के आधार पर वार्डों का परिसीमन कर सभी विधानसभाओं में वार्डों की संख्या एक समान रखी जाए। ❑❑

साल दर साल कैसे बदला भारतीय शहरों की रैंकिंग

शहर	2017	2018	2019	2020	2021
भिवाड़ी	-	05	16	04	01
गाज़ियाबाद	02	02	01	02	02
दिल्ली	11	11	04	09	04
नोएडा	03	06	05	05	07
भावलपुर	-	-	-	18	8
हिसार	-	-	21	13	11
फरीदाबाद	06	04	15	10	12
ग्रेटर नोएडा	-	-	07	06	13
रोहतक	18	23	55	24	14
लखनऊ	08	09	08	08	16
जींद	05	18	14	12	17
गुरुग्राम	01	01	06	22	18
कानपुर	07	19	122	07	20

दिल्ली सबसे प्रदूषित, यहां पर सांस लेना घातक

दुनियाभर के सबसे प्रदूषित देशों में भारत का स्थान पांचवां है।, वहीं शहरों की बात करें तो राजधानी दिल्ली प्रदूषित शहरों में दुनिया में चौथे पायदान पर है। वहीं देशों की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा भी दिल्ली के नाम पर है। यह रिपोर्ट आईक्यूएयर ने हाल में जारी की थी। रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में 2021 में प्रदूषण का सतर 14.6 प्रतिशत बढ़ा है। 2020 में यह 84 एमजीसीएम था जो 2021 में बढ़कर 96.4 एमजीसीएम पर पहुंच गया है।

रिपोर्ट के अनुसार 2018, 19 और 20 में प्रदूषण के राष्ट्रीय स्तर में कमी दर्ज की गई थी, लेकिन 2021 में यह दोबारा बढ़ गया है। यह वापस से 2019 के स्तर के करीब पहुंचने लगा है, जो कोविड से पहले का समय था। वहीं भारत का कोई भी शहर डब्ल्यूएचओ के मानकों के करीब तक नहीं है। भारत के 48 प्रतिशत शहरों में डब्ल्यूएचओ के मानकों में दस गुना अधिक प्रदूषण है।

संपादकीय
शांति मिशन

नेक कामों में जमिअत उलेमा हिन्द का सहयोग कीजिए

हिन्दोस्तान की मुस्लिम संस्थाओं के इतिहास में जमीअत उलेमा हिन्द को यह गौरव प्राप्त है कि उसने अपनी स्थापना के प्रथम दिन से ही भारतीय मुसलमानों का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन का फर्ज़ अंजाम दिया है स्वतंत्रता से पहले जहां उसने ब्रिटेन साम्राज्य की ज़्यादतियों का मुक़ाबला किया वहीं उसे अपनों की आलोचना को भी बर्दाश्त करना पड़ा। यह जमीअत-उलेमा-ए-हिन्द ही थी जिसने इस वक्त सम्पूर्ण आज़ादी की मांग रखी थी जब देश की तमाम पुरानी संस्थाएं कांग्रेस सहित थोड़ी-सी आजादी और कुछ सुख-सुविधाएं प्राप्त कर लेना ही गौरव की बात सोचा करती थीं।

जमीअत-उलेमा-ए-हिन्द ने आज़ादी से पहले सत्तारूढ़ ब्रिटेन साम्राज्य के नेतृत्व संरक्षण में काम करने वाली ईसाई मिशनरियों का डटकर मुक़ाबला किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करके साबित कर दिया कि दुनिया की कोई ताक़त मुसलमानों के दीन व ईमान और मज़हब को उनसे नहीं छीन सकती और जब अंग्रेजी साम्राज्य ने मुसलमानों के वर्चस्व को मिटाने के लिए विभिन्न धर्मों की आपसी शादियों को परवान चढ़ाने के लिए कानून बनाने की कोशिश की तो यह जमीअत उलेमा हिन्द ही थी जिस ने बड़ी हिम्मत के साथ ब्रिटेन साम्राज्य का मुक़ाबला किया और इस मसले को इंग्लैण्ड में होने वाली गोलमेज़ कांफ्रेंस तक पहुंचाकर इस कानून को निरस्त कराने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद फितना-ए-इरतदाद को हवा दी गयी। इस्लामी शरिअत के ख़िलाफ़ शारदा एक्ट लाया गया। बैतुल्लाह की ज़ियारत और हज को जाने वाले मुसलमानों की राह में अनेक कठिनाईयां खड़ी की गयीं लेकिन जमीअत उलेमा हिन्द ने किसी एक अवसर पर भी मुसलमानों को बेसहारा नहीं छोड़ा। इस तरह उसने ब्रिटेन साम्राज्य के जुल्म अत्याचारों की परवाह किए बग़ैर आज़माईश की हर घड़ी में मुसलमानों की दीनी, शरई और सियासी रहनुमाई का शानदार फरीज़ां अंजाम देकर एक ऐसा इतिहास बनाया है जिसको आने वाला इतिहासकार, लेखक कभी भुला नहीं सकता और आज जमीअत उलेमा हिन्द के यही कारनामें और ख़िदमात हैं जो पूरी दुनिया में शोध का विषय बने हुए हैं।

एक लम्बे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता मिली, लेकिन वह अपने साथ देश बंटवारे की दु:खद घटना भी लेकर आयी जिसके नतीजे में जहां लाखों लोग देश छोड़कर दूसरे देश में चले गए वहीं सम्पत्ति का बंटवारा भी एक बड़ा मसला बनकर उभरा। इस मसले को हल करने के लिए भारत सरकार ने कस्टोडियन का महकमा क़ायम किया, जिसने अत्याधिक पक्षपात का प्रदर्शन करते हुए मुसलमानों को बड़े पैमाने पर अत्याचारों का शिकार बनाना शुरू कर दिया और मुसलमानों की जायदादों दुकानों और मकानों को खुद उनकी आंखों के सामने टके के भाव नीलाम करना शुरू कर दिया, इस समय जिस जमात ने मुसलमानों की हिमायत व हमदर्दी की वह जमीअत-उलेमा-ए-हिन्द ही थी जिसने कस्टोडियन के पुलिस अफसरों के बेदर्द कलम को पकड़ा और उन्हें मजबूर कर दिया कि वो मुसलमानों के साथ इंसाफ से काम लें। अकाबिर जमिअत की यह कोशिशें रंग लाईं औरयह कहना कुछ अतिश्योक्ति न होगा कि आज जो मुसलमान अपनी जायदादों पर बैठें हुए हैं यह जमीअत उलेमा हिन्द और उसके हिम्मती नेतृत्व का ही फल है। किसी न किसी तरह कस्टोडियन का महकमा तोड़ा गया मगर अभी मुसलमानों को सकून भी मयस्सर न आया था कि मुस्लिम औक़ाफ़ पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जाने लगे। जमीअत उलेमा हिन्द और उसके अकाबिर उठे और उन्होंने पूरे मुल्क़ में सरकार के इस गलत कदम के ख़िलाफ़ जन सहमति बनायी और उसके बाद सरकार को एक कानून बनाने पर मजबूर किया। यह वक़्फ़ कानून अगरचे जमीअत उलेमा हिन्द के ख़्वाबों का आइनादार तो नहीं था लेकिन फिर भी एक हद तक औक़ाफ़ के तहफ्फुज़ में मददगार साबित हुआ और कम से कम औक़ाफ़ कुछ हद तक सुरक्षित हो गए। अल्गरज़ साम्प्रदायिक दंगें हों या शरिअत का तहफ्फुज़ मामला, मुसलमानों के तालीमी व आर्थिक मसायल के हल का मामला हो या भारतीय मुसलमानों की नागरिकता का सवाल, जमीअत-उलेमा-ए-हिन्द ने आगे बढ़कर हर मामले में मुसलमानों की रहनुमाई का फर्ज़ अंजाम दिया है।

जमीअत-उलेमा-ए-हिन्द मुसलमानों के आधुनिक मसायल से भी कभी ग़ाफ़िल नहीं रही इसने एक मुबाहिश फकीयह का शोबा क़ायम किया जिसके तहत आधुनिक मसायल में मुसलमानों की रहनुमाई की जाती है। जमीअत-उलेमा-ए-हिन्द ने इस शोबे के तहत विभिन्न विद्वानों के अनेक इज्तमा आयोजित करके बहुत से ऐसे मसायल हल किए हैं जिन्हें अभी तक हल न होने वाला समझा जाता था।

बेवाओं की मदद व आर्थिक रूप से कमज़ोर मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए वज़ीफ़ों का इंतज़ाम, दीनी मदरसों के विद्यार्थियों का सहयोग और साम्प्रदायिक दंगों यानि विभिन्न तरह की आपदा के शिकार बेघर-बार बेसहारा होने वाले मुसलमानों की मदद व पुनर्वास इत्यादि जमीअत-उलेमा-ए-हिन्द के ऐसे मिल्ली काम हैं जिनसे हर शख़्स वाक़िफ़ है इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के इरतदादज़दा इलाकों में मस्जिदों की तामीर और मदरसों की स्थापना के कार्य जमीअत-उलेमा-ए-हिन्द के वह कारनामें हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इन मस्जिदों और मदरसों की तामीर और फिर उनमें इमाम मोअज़्ज़न और अध्यापकों का सम्पूर्ण प्रबंध पूरे तौर पर जमीअत उलेमा हिन्द की तरफ से ही किया जाता है। साम्प्रदायिक शक्तियों के संरक्षण में कादियानियत, इसाईयत और इरतदाद के हमलों का मुक़ाबला भी जमीअत उलेमा हिन्द के प्रमुख कारनामों में गिना जा सकता है। क़ादियानियत और दूसरे बातिल फिरक़ों के मुक़ाबले के लिए जमीअत उलेमा हिन्द ने मुल्कगीर तहरीक़ शुरू की। मुल्क़ के विभिन्न भागों विशेषकर राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा और उ.प्र. में प्रशिक्षण कैम्प लगाये गए जिनके अच्छे प्रभावी नतीजे आ रहे हैं और झूठी बातिल ताक़तें पिछड़ने पर मजबूर हो रही हैं। मुस्लिम वर्ग में आने वाली ख़राबियों को दूर करने के लिए जमीअत उलेमा हिन्द ने इस्लाहे मुआशरा प्रोग्राम शुरू किया और यह कहना अतिश्योक्ति न होगा कि अगर आज पूरे देश में हर तंज़ीम और जमाअत का यह एक बुनियादी प्रोग्राम बन चुका है तो यह जमीअत उलेमा हिन्द की बुनियादी जद्दोजहद का ही नतीजा है। जमीअत उलेमा हिन्द मुल्क़ भर में हर साल इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर, हफ्ता, अशरा और पन्द्रह दिनी प्रोग्राम मुरत्तब करके इसके लिए हज़रात उलेमा कराम की ख़िदमात हासिल करती है और एक ही वक़्त में देश के कोने-कोने में मुसलमानों तक यह पैग़ाम पहुँचाने की कोशिश करती है कि इस्लाम और उसकी तालिमात पर अमल ही दुनिया और आख़िरत की कामयाबी का प्रमाण है।

जमीअत-उलेमा-ए-हिन्द की भूमिका सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है इसने हिन्दोस्तानी मुसलमानों को रिश्ता अख़वत में मुन्सलिक करने के लिए पूरी इस्लामी दुनिया के मसायल से दिलचस्पी ली है। फिलस्तीन का मसला हो या इराक़ व अफग़ानिस्तान का सोमालिया के मुसलमानों के मामलात हों या चेचन्या कोसोवो और बोस्निया के मामलात, जमीअत उलेमा हिन्द ने इन तमाम देशों के मुसलमानों के साथ इज़हारे यक्ज़हती करके पूरी दुनिया में हिन्दोस्तानी मुसलमानों का नाम रोशन किया है।

इस तरह यह कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि जमीअत-उलेमा-ए-हिन्द और उसकी क़यादत की मिसाल एक छायादार वृक्ष जैसी है जिससे अपने और पराए सब ही लाभ उठाते हैं। जमीअत उलेमा हिन्द तो उससे भी कहीं आगे जाना चाहती है इस के तामीरी व आर्थिक मंसूबे अगर आप गौर फरमाएं तो उसकी मंसूबाबंदी और मिल्ली तामीर व तरक्क़ी के लिए फिक्रमंदी पर आप हैरान रह जाएंगे मगर अफसोस कि इसके पास इन मंसूबों की तकमील के लिए पैसे और फण्ड की इस क़दर कमी है कि वह हज़ार ख़्वाहिशों के बावजूद जब तक उसे मिल्लते इस्लामिया का भरपूर सहयोग हासिल न हो वह अपने मंसूबों को अंतिम मंज़िल तक नहीं पहुंचा सकती।

रमज़ानुल मुबारक का पवित्र महीना हमारे सिरों पर साया किए हुए है इस मुबारक महीने में हर मुसलमान दीनी व फलाही कामों के लिए कम या ज़्यादा अपनी सामर्थ्य के अनुसार खर्च करता ही है इसलिए जमीअत उलेमा हिन्द की यह अपील समयनुसार और क़ाबिले ग़ौर है कि उसे इसके मंसूबों की तकमील के लिए अपने भरपूर तआव्वुन से नवाज़ें। हमें उम्मीद है कि आप उम्मत के उन बरगुज़िदा बन्दों की जमाअत जमीअत उलेमा हिन्द की आवाज़ पर अपनी तवज्जो देंगे। याद रखिए मिल्ली कामों के लिए ख़र्च करना खुद अपनी सुरक्षा व संरक्षा के लिए ख़र्च करना है फिर जमीअत उलेमा हिन्द और उसके अकाबिर का तो मुख्य उद्देश्य ही भारतीय मुसलमानों की तरक्क़ी और इस्लामी संस्कृति की सुरक्षा करना व मिल्लते इस्लामिया की तरक्की है। ऐसे हालात में यह कहना कोई अतिश्योक्ति न होगा कि अगर आपने अपनी पाक कमाई का एक हिस्सा मिल्लत के फलाही कामों पर ख़र्च न किया तो शायद आप तख़्लीक़ कायनात के मफहूम से नाआशना (अंजान) ही रहे हैं।

गो नाला नारसा हो न हो आह में असर
मैंने तो दगुज़र न की जो मुझसे हो सका

हज़रत उमर रज़ि॰ का फौजी निज़ाम

फौजी छावनियाँ किस उसूल पर क़ायम थी

इसी तरह और सैकड़ों छावनियाँ जाबजा क़ायम हो गई जिनकी तफसील की चंदा ज़रूरत नहीं, अलबत्ता इस मौक़े पर ये बात लिहाज़ के क़ाबिल है कि इस सिलसिले को इस क़दर वसअत क्यों दी गई थी और फौजी मक़ामात के इंतख़ाब में क्या उसूल मलहूजा थे? असल ये है कि जिस वक्त तक इस्लाम की फौजी ताक़त ने अगरचे बहुत ज़ोर और वसअत हासिल कर ली थी लेकिन बाहरी ताक़त का कुछ सामान न था, इधर यूनानी मुद्दत से इस फन में माहिर होते आये थे इस वजह से शाम और मिस्र में अगरचे किसी अंदरूनी बग़ावत का कुछ अंदेशा न था क्योंकि अहले मुल्क बावजूद इख़्तलाफ़ मज़हब के मुसलमानों को इसाईयों से ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन रोमियों के बाहरी हमलों का हमेशा खटका लगा रहता था, इसके साथ ही एशिया कोचक अभी तक रोमियों के कब्ज़े में था और वहां इनकी ताक़त को कोई सदमा नहीं पहुंचा था, इनके वजूद से ज़रूर था कि सरहदी मक़ामात और बंदरगाहों को निहायत मुस्तहकम बनाया जाये।

यही वजह थी कि हज़रत उमर रज़ि॰ ने जिस क़दर फौजी छावनियाँ क़ायम थी इन्हीं स्थानों पर की जो साहिल पर वाके थे या एशियाये कोचक के नाके पर थे, इराक़ की हालत इससे अलग थी, क्योंकि वहां सल्तनत के सिवा देश के बड़े-बड़े रईस जो मरज़बान कहलाते थे अपनी वकाये रियासत के लिये लड़ते रहते थे और दबकरमती भी हो जाते थे तो इनकी इताअत पर इत्मीनान नहीं हो सकता था, इसलिये इन मुमालिक में हर जगह फौजी सिलसिला क़ायम रखना ज़रूरी था कि मुदईयान रियासत बग़ावत का ख़्वाब न देखने पाये। (जारी)

20 लाख नौकरियां देने में प्राइवेट सेक्टर से लेंगे मदद

मनीष सिसौदिया

स्वराज बजट, ग्रीन बजट, देशभक्ति बजट के बाद आम आदमी पार्टी ने 2022-23 में रोज़गार बजट पेश किया है और 05 वर्ष में बीस लाख नई नौकरियों का बड़ा लक्ष्य रखा है। इतनी बड़ी तादाद में नई नौकरियों के रोडमैप, शहर के प्रमुख खुदरा बाज़ारों का कायाकल्प, शॉपिंग फेस्टिवल के फायदों से लेकर बजट के विभिन्न पहलुओं पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया जी से बातचीत हुई, पेश है इस बातचीत के प्रमुख अंश।

सवाल:- रोज़गार बजट को लेकर सरकार की क्या सोच है?

जवाब:- दिल्ली सरकार की सोच यह है कि इस समय देश के लोगों की सबसे बड़ी समस्या और ज़रूरत रोज़गार है। अभी तक कोई सरकार इसका समाधान नहीं दे पाई है। जैसे कोई सरकार बिजली व्यवस्था ठीक नहीं कर पाई, कोई सरकार स्कूल अस्पताल ठीक नहीं कर पा रही थी, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने 7 साल में स्कूल-अस्पतालों में बड़े बदलाव कर लोगों का जीवन आसान बनाया है। वैसे भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सोच है कि रोज़गार का समाधान देना है। रोज़गार बजट तैयार करने में सरकार ने पहले बहुत रिसर्च की है। 6 महीने में दिल्ली सरकार की इकॉनोमी टीम ने दुकानदारों, विभिन्न संगठनों के साथ 150 बैठक कर इतने बड़े पैमाने पर नई नौकरियां पैदा करने का रोडमैप बनाया है।, 6500 सुझावों को स्टडी करने के बाद रोज़गार बजट सामने आया है। नई नौकरियां पैदा करने के लिए मुख्य रूप से 8 क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें खुदरा क्षेत्र, खाद्य एवं पेय पदार्थ, यात्रा एवं पर्यटन, निर्माण, रियल एस्टेट, ग्रीन एनर्जी, मनोरंजन, लॉजिस्टिक व सप्लाई चैन शामिल है।

सवाल:- 05 साल में 20 लाख नौकरियां पैदा करने को आप कैसे देखते हैं, क्या इस मिशन को पूरा कर पाएंगे?

जवाब:- चुनौती को स्वीकार करने का नाम ही अरविंद केजरीवाल है। केजरीवाल ने चुनौती स्वीकार की है कि 05 वर्ष में 20 लाख नौकरी लोगों को मिलेंगी। दिल्ली के बाज़ारों में सरकार की पॉलिसी को लेकर जाना होगा। प्राइवेट सेक्टर में बड़ी संख्या में नौकरियां लाने का स्कोप है। इस समय प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों के पास नौकरियां नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को सरकार की पॉलिसी का फायदा मिलेगा और उसके बाद रोज़गार के अवसरों में इज़ाफा होगा। सरकारी नौकरी तो सीमित है। ज़रूरत कि हिसाब से सरकारी नौकरी निकलती है और सरकार उन पोस्ट को तेज़ी से भर्ती भी है। सरकार ने विभिन्न विभागों व संस्थानों में 1.78 लाख से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं, इसमें से 51.307 पक्की सरकारी नौकरियां रहीं हैं। सरकारी विभागों में ज़रूरत के हिसाब से वेकैंसी निकलती है। प्राइवेट सेक्टर में काफी स्पेस है और सरकार इसके लिए आसान नीतियों और प्रोत्साहन देकर रोज़गार के अवसरों को बढ़ाएगी।

सवाल:- रोज़गार बजट मतें पांच बड़े खुदरा बाज़ारों को नया रूप देने की घोषणा की गई है, ये कौन से बाज़ार होंगे और कब तक योजना को मुक़ाम तक पहुंचाया जा सकेगा?

जवाब:- सरकार बाज़ारों के संगठन, बाज़ारों के लोगों से बात करके यह यह करेगी कि पहले चरण में दिल्ली के कौन से 05 खुदरा बाजारों को नया रूप दिया जाएगा। सरकार पब्लिक नोटिस जारी कर बाज़ार एसोसिएशन और संगठनों से पूछेगी कि वे बताएं कि इस योजना में वे कैसे शामिल होना चाहते हैं? अभी बहुत सारे सुझाव सरकार को मिले हें, लेकिन सरकार बाजारों संगठनों से बातचीत कर फैसला लेगी। प्रतिष्ठित रिटेल बाज़ारों में से 5 को चुना जाएगा।

सवाल:- दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल के आयोजन का मक़सद क्या है और ये फेस्टिवल कैसे होंगे?

जवाब:- दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल और होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल के लिए 250 करोड़ का बजट रखा गया है जो दिल्ली से होलसेल का सामान लेकर जाते हैं, उनके लिए आकर्षक योजनाएं होंगी, दिल्ली के बाज़ारों को आगे बढ़ाने में दिल्ली सरकार की अहम भूमिका रहेगी। यहां पर मनोरंजन, बिजनेस चर्चा, टूरिज़्म इवेंट होंगे।

सवाल:- मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को सरकार कैसे आगे बढ़ाएंगी?

जवाब:- पिछली बार इसका बजट 15 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 50 करोड़ किया गया है। सरकार ने बजट में काफी इज़ाफा किया है और जैसे-जैसे ट्रेन मिलती रहेंगी, वैसे-वैसे शेडयूल तय किया जाएगा।

सवाल:- रोज़गार बाजार पार्ट 2.0 कब तक शुरू हो पाएगा?

जवाब:- रोज़गार बाज़ार पोर्टल को आधुनिक और प्रफेशनल तरीके से रोज़गार बाजार 2.0 के रूप में लाया जाएगा। यह ऑन लाइन होगा और यहां पर रोज़गार के अवसरों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी।

सवाल:- बड़े बाज़ारों में क्या बदलाव होंगे.?

जवाब:- जिस तरह से गांधी नगर को गारमेंट हब के रूप में डिवेलप किया जाएगा और इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट भी रखा है, उसी तरह से 5 बाज़ारों में हर छोटी से बड़ी समस्या को दूर किया जाएगा। इन बाज़ारों में ट्रेफिक मैनेजमेंट को बेहतर करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोग आसानी से आ जा सके। बिजली के तारों की समस्या को दूर किया जाएगा। सिविक समस्याओं को दूर किया जाएगा। बाज़ार संगठनों के सुझावों के आधार पर बाज़ार का प्लान तैयार किया जाएगा।

सवाल:- शिक्षा का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कम है?

जवाब:- शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में है। इस बार जब बजट का साइज बढ़ाया है तो शिक्षा क बजट सबसे ज़्यादा रहा है। आज भी सबसे ज़्यादा शिक्षा का बजट है। शिक्षा में इन्फ्रास्ट्रक्चर में काफी काम हो गया है और अब पानी, सड़क समेत दूसरे सेक्टर में इंफ्रास्क्ट्रचर में काफी काम होना है। एक बात तय है कि एजूकेशन और हेल्थ को जितने पैसे की ज़रूरत होगी, सबसे पहले उस ज़रूरत को पूरा किया जाएगा।

सवाल:- एक हज़ार मोहल्ला क्लिनिकल का लक्ष्य कब पूरा किया जा सकेगा.?

जवाब:- कोविड के कारण लॉकडाउन के चलते मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट में कुछ देरी हुई है। अब तेज़ी से मोहल्ला क्लिनिक बनाए जा रहे हैं। एक हज़ार का लक्ष्य अगले एक से दो साल में पूरा हो जाएगा। महिला मोहल्ला क्लिनिक की योजना पर तेज़ी से काम हो रहा है इस वर्ष ये क्लिनिक बन जाएंगे।

सवाल:- फूड ट्रक पॉलिसी कब लागू होगी.?

जवाब:- जल्द ही फूड ट्रक की पॉलिसी बन जाएगी। अभी मुंबई, गुड़गांव में फूड ट्रक है। दिल्ली सरकार की योजना है कि इन फूड ट्रक के ज़रिए लोगों को रात के समय क्वॉलिटी फूड मिले। ये ट्रक रात को 8 से दो बजे तक संचालित होंगे। सरकार की पॉलिसी के तहत अलग-अलग जगहों पर फूड ट्रक खड़े होंगे, जहां पर क्वॉलिटी फूड दिया जाएगा।

सवाल:- एनसीडी बिल को लेकर सरकार कोर्ट में जाने की बात भी कह रही है, इस पर आपका क्या कहना है.?

जवाब:- यह चुनाव से भागने का बिल हैं बिल के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के बाद सरकार तय करेगी कि कोर्ट में कैसे चुनौती देंगे। यह बिल केवल चुनाव को टालने के लिए लाया जाएगा। ❑❑

एनडीए सरकार को किसी तरह का ख़तरा नहीं है

भाजपा के सीनियर लीडर शाहनवाज़ हुसैन

बिहार की राजनीति में गहमा गहमी चल रही हैं सरकार में शामिल विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के चीफ और नीतीश सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने पिछले दिनों तेजस्वी यादव को ढाई-ढाई साल सरकार चलाने का ऑफर देकर एनडीए को असहज कर दिया था। इसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि वीआईपी के सभी तीन विधायकों ने भाजपा जॉइन कर ली। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि देर-सबेर ऐसा ही जीतन राम मांझी की पार्टी में भी होना है। इसे नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ने के नज़रिए से देखा जा रहा है, जो कि भाजपा के मुक़ाबले सदन में कम संख्या बल होने के बावजूद मुख्यमंत्री हैं। बिहार में जो कुछ चल रहा है, उसकी वजह क्या है और आगे क्या हो सकता है, पेश है इन तमाम मुद्दों पर भाजपा के सीनियर लीडर शाहनवाज़ हुसैन से हुई एक बातचीत के प्रमुख अंश।

सवाल:- आप लोगों पर इल्ज़ाम है कि आपने अपने एक सहयोगी की पार्टी तोड़ दी। उनके सारे विधायकों को अपने पाले में कर लिया। ऐसा करना क्यों ज़रूरी हुआ.?

जवाब:- तोड़ना शब्द का इस्तेमाल ग़लत है। हमने मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़ा नहीं हैं उनके विधायकों ने 'घर वापसी' की है। यह जो तीन विधायक विकासशील इंसान पार्टी को छोड़कर भाजपा में आए हैं, वे मूल रूप से भाजपा के ही हैं। विधानसभा चुनाव के समय जब सीटों का बंटवारा हुआ तो मुकेश सहनी के पास चुनाव जीतने वाले लोग ही नहीं थे तो कुछ सीटों पर हमने अपने आदमी दिए थे। हमारे ही आदमी चुनाव जीते, उनके तो सब हार गए थे।

सवाल:- बिहार में एक के लिए उपचुनाव होना है। वह सीट वीआईपी कोटे की है लेकिन भाजपा ने उस पर अपना उम्मीदवार उतार दिया। यह अविश्वास क्यों?

जवाब:- मुकेश सहनी की पार्टी ऐसी है जिसके पास चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं होते लेकिन उन्हें चुनाव के लिए सीट चाहिए होती है। उपचुनाव में भी वह जिसे उम्मीदवार बना रहे थे, वह आरजेडी में शामिल हो गया। चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता है और न ही हम तमाशबीन बनकर बैठ सकते हैं। प्रतिष्ठा तो एनडीए की दांव पर लगी होगी, इसलिए हमने अपना उम्मीदवार दिया।

सवाल:- कहा जा रहा है कि यह जो विधायकों वाला घटनाक्रम है, उसकी वजह मुकेश सहनी का तेजस्वी यादव को ढाई वर्ष का सीएम बनने के लिए दिया गया ऑफर है.?

जवाब:- उनके ऑफर को आरजेडी ने भी गंभीरता से नहीं लिया तो हम क्यों लेने लग जाते। सबको पता है कि मुकेश सहनी बिहार की राहनीति में कितनी गंभीरता रखते हैं। सबेरे कुछ बोलते हैं और शाम को कुछ और हो जाते हैं। सरकार बनाने और बिगाड़ने की हैसियत तो उस व्यक्ति या पार्टी के पास होती है, जिसके पास विधायक होते हैं। तकनीकी रूप से अभी तक मुकेश सहनी की पार्टी में तो तीन विधायक थे भी, उनकी मुकेश सहनी से एक वर्ष तक बातचीत तक नहीं हो पा रही थी। वे मानसिक रूप से भाजपा के साथ ही थे। ऐसे में यह किसको ढाई वर्ष के लिए मुख्यमंत्री बनवा पाते और कौन इन्हें ढाई वर्ष का मुख्यमंत्री स्वीकार कर लेता? वेसे भी बिहार विधान सभा में सदस्यों का जो गणित है, उसमें

सवाल:- चर्चा है कि देर सबेर जीतन राम मांझी की पार्टी के साथ भी ऐसा हो सकता है?

जवाब:- ऐसा नहीं होने वाला जीतन राम मांझी गंभीर और बिहार की राजनीति को समझने वाले नेता हैं। वह हमारे बहुत विश्वसनीय सहयोगी है। मुकेश सहनी के साथ भी यह नौबत नहीं आती। उनके साथ ऐसा इसलिए हुआ कि उनके विधायक

बाक़ी पेज 11 पर

लोकतंत्र की ताक़त पारदर्शिता क्या भारत की नीतियों में हैं

लोकतंत्र की ताक़त पारदर्शिता है। जब लोगों को पता होता है कि देश किसी कठिनाई का सामना कर रहा है, वे इससे मिलकर लड़ सकते हैं। वे यह जानकर करीब आ जाते हैं कि वे संयुक्त रूप से ख़तरे का सामना कर रहे हैं। यद्यपि यह भावना संभव है, मगर एक ऐसे देश में इसे प्राप्त करना संभव नहीं जहां लोकतंत्र नहीं क्योंकि अधिनायकवाद नेतृत्व गोपनीयता रखता है।

इसका एक उदाहरण यूरोप में लड़े जा रहे युद्ध में दिखाई देता है। सारा यूक्रेन एकजुट हो गया है तथा दुनिया विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए इसकी हिम्मत देख रही है। निश्चित तौर पर जिस तरह से यूक्रेन अपने वर्तमान लोकतंत्र तक पहुंचा है इसे लेकर विवाद हो सकता है तथा यह भी एक कारण है कि रूस ने इस पर हमला किया। मगर इसे लेकर कोई विवाद नहीं कि दोनों देशों में पारदर्शिता को लेकर कितना अंतर है।

यूक्रेनियन जानते हैं कि वे किस चीज़ का सामना कर रहे हैं और इसका मुक़ाबला करने के लिए वे एकुट हो गए हैं। रूस ने अपने नागरिकों की फेसबुक पर पहुंच को अवरुद्ध कर दिया क्योंकि व्लादिमीर पुतिन नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है। उन्होंने एक कानून भी लागू किया है जिसमें सेना पर रिपोर्टिंग करने के लिए मीडिया संगठनों को 15 वर्ष की जेल हो सकती है। यह बहुत से रूसियों के लिए चिंता पैदा कर सकता है तथा दीर्घकाल में देश के लिए हानिकारक होगा।

25 मार्च को चीनी विदेश मंत्री भारत आए। सरकार का कहना है कि यह एक अघोषित दौरा था यद्यपि मीडिया को जानकारी थी कि वांग यी आ रहे हैं उन्होंने हमारे विदेश मंत्री तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी मुलाक़ात की इसलिए उनके दौरे का विषय गोपनीय नहीं था, यह थी लद्दाख में स्थित। वांग ने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कहा लेकिन इसकी इजाज़त नहीं दी गई, बहाना यह लगाया गया कि मोदी, योगी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए उत्तर प्रदेश में थे। यह हमारे लिए एक दूसरा संकेत है कि भारत स्थिति को लेकर खुश नहीं है। क्या है यह स्थिति? यह एक समस्या है। ख़ुद प्रधानमंत्री ने भारतीयों को बताया कि कोई समस्या नहीं है तथा कोई भी हमारे क्षेत्र में नहीं घुसा। रक्षामंत्री ने कहा कि कोई भी भारत के सैनिकों को उन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग से नहीं रोक रहा जहां वे ऐतिहासिक तौर पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं।

यदि यह मामला है तो चीनियों के साथ क्या बात करनी है? यही वह चीज है जो सरकार हमें नहीं बता रही। जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, ने कहा कि यह चीनी पक्ष था जो सेनाओं को पीछे हटाना चाहता था तथा ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान स्थिति पारस्परिक हित में नहीं था। कहां से सेनाएं पीछे हटाना? यदि वे अपने क्षेत्र में हैं तो वास्तव में कोई समस्या नहीं है। 11 मार्च को भारतीय सेना तथा चीनी सेना के जनरल 2020 के झगड़े के बाद से बातचीत के 15वें दौर के लिए मिले। यदि कोई घुसपैठ ही नहीं है तो वे किस बारे में बात करते हैं? हमारी सरकार ने यह नहीं बताया।

इसके एक दिन बाद अंग्रेज़ी के एक समाचार पत्र ने रिपोर्ट दी कि हॉट स्प्रिंग्स में दोनों पक्षों के पालटून आकार की ताक़त में सैनिक हैं लेकिन चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय पक्ष में है। सरकार ने इस रिपोर्ट का खंडन नहीं किया और न ही इस पर टिप्पणी की। सेवानिवृत्त जनरलों, जो लिखते है।, सहित अधिकांश विशेषज्ञों की राय है कि भारतीय ज़मीन पर अतिक्रमण हुआ है तथा चीन इसे ख़ाली करने से इंकार कर रहा है और यही समस्या है।

कुछ ने लिखा है कि इस समस्या में वृद्धि हो सकती है तथा चीनी ही ऐसा करेंगे। ऐसे भी समाचार हैं कि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के नए क्षेत्रों में अतिक्रमण किया है। (जिस पर चीन दावे जताता है क्योंकि तिब्बत के छठे दलाई लामा का 1683 में तवांग में जन्म हुआ था।)

रूस की तरह चीन में तानाशाही है और यह पारदर्शिता पसंद नहीं करता। भारत एक लोकतंत्र है लेकिन हमने (अन्यों के साथ) इस मुद्दे पर पारदर्शितापूर्ण नहीं होना चुना, कारण जो भी हो। मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि क्यों, यद्यपि यह काफी स्पष्ट है इसका कारण क्या है।

हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि भारत एक तानाशाही नहीं है तथा इसे एक लोकतंत्र के तौर पर अपनी स्वाभाविक ताक़त का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ कारणों से हम नहीं कर रहे और दरअसल ऐसा लगता है कि हम ख़ुद को गुमराह कर रहे हैं और चीन को स्थान दे रहे हैं। पेइचिंग में बैठे विदेश नीति विशेषज्ञों ने भारतीय सरकार द्वारा उत्पन्न दुविधा पर गौर किया होगा। इस बात की संभावना नहीं है कि उन्होंने इस बात का आंकलन नहीं किया होगा कि कैसे इसका इस्तेमाल उनके लाभ के लिए किया जा सकता है। चीन क्या चाहता है और क्यों 2 सालों से लद्दाख सीमा पर गर्माहट बनी हुई तथा अरुणाचल प्रदेश में क्या चल रहा है? इस सबका उस सड़क के साथ क्या लेना-देना है जो चीन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बनाई है जो पश्चिमी चीन को बलूचिस्तान के साथ जोड़ती है?

चीन का श्रीलंका में एक बंदरगाह पर नियंत्रण है तथा बंग्लादेश के समाचार पत्र चीन की बैल्ट एंड रोड योजना में शामिल होने को लेकर सकारात्मक रिपोर्टों से भरे हैं। नेपाल भी इस योजना का एक हिस्सा है। दक्षिण एशिया में अकेले भारत तथा भूटान ने इसमें शामिल होने से इंकार किया है। भारत के दीर्घकालिक भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ है तथा वे

बाक़ी पेज 11 पर

'जीआईएस' अवसरों की भरमार

जी आईएस एक नया व अहम फील्ड है जो युवा वर्ग को एक असीमित संभावनाओं से युक्त माहौल में कार्य करने का अवसर देता है। एक ऐसा वातावरण जो मैथड, मेप मेकिंग और कार्टोग्राफी, इमेजिंग एवं इमेज इंटरप्रिटेशन, डाटाबेस एवं कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को परस्पर जोड़ता है। ये सब विषय इसके तहत आकर एक साथ जुड़ जाते हैं। पहले सब यह सोचते थे कि जीआईएस के इस्तेमाल से केवल नक्शों का निर्माण होता है, केवल आजकल जीआईएस की सीमाएं दूर तक फैल गयी हैं।

स्कोप

जीआईएस के क्षेत्र में कार्टोग्राम, चार्ट, कस्टमर लिस्ट, थ्रीडी डायग्राम और मूवीज शामिल हैं। कार्टोग्राम एक ऐसे विशेष मेप होते हैं जिनमें भूमि और दूरी दोनों वेरिएबल होती हैं। चार्ट के कई प्रकार पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट व पिक्चर है। इसी वजह से 21वीं सदी के संगठनों के लिए जीआईएस एक अहम टूल (औजार) है। इन्हीं संगठनों में काम करके कैरिअर बनता है। कई कंपनियां जीआईएस सिस्टम्स को अंगीकार व विकसित कर रही हैं और इसकी एप्लीकेशन पर ध्यान दे रही हैं।

यह सिस्टम्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्पेशियल डेटा का इस्तेमाल भौगोलिक संदर्भ वाली सूचनाएं प्राप्त करने, मैनेज करने, विश्लेषण करने और प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। स्पेशियल डेटा में सेटेलाइट इमेज, एरियल फोटो, जनसंख्या के आंकड़े, कस्टमर एवं कंज्यूमर डेटा और सेंसर बेस्ड डेटा शामिल हैं। जीआईएस डेटा विभिन्न तरह से संगठनों की, डेटा आब्जर्व करने, समझने, प्रश्नावली बनाने, डेटा निकालने और प्रस्तुत करने में मदद करता है। इस सबकी सहायता से परस्पर संबंधों, सहायता से परस्पर व प्लॉटर का खुलासा होता है। इससे जल्दी कुशलता, जल्दी व आसानी से समझा जा सकने वाला विजुअल कम्युनिकेशन तथा अच्छे निर्णय लेने में मदद मिल रही है।

बढ़ता दायरा

दरअसल, जीआईएस की एप्लिकेशन की राष्ट्रीय व सामाजिक तौर पर खास महत्ता है। ये सस्टेनेबल डिवेलपमेंट रणनीति निर्माण, संगठनों की बिजनेस प्रोसेस को बेहतर तरह से मैनेज करने में सक्षम बनाने और आम व्यक्ति तक भौगोलिक ज्ञान पहुंचाने में सरकारों के लिए मददगार हैं।

मिसाल के तौर पर, भारत में एक कंपनी समुद्री के स्तर में बढ़ोत्तरी के भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रभाव जानने के लिए जीआईएस का इस्तेमाल करती है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने का प्रभाव तय करने हेतु विश्लेषण के दौरान थर्मल एक्सपेंशन और ग्लेशियरों के पिघलने जैसी दो वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है। प्रभावित जनसंख्या पर मैपिंग की जाती है और जनसंख्या संबंधी सूचनाओं व गणनाओं का उपयोग करके प्रभावित लोगों के लिए सुरक्षित स्थान तय किये जाते हैं। इसी तरह से सन 2011 में सुनामी से जान माल की हानि हुई भारी क्षति का आंकलन करने में जीआईएस ने अहम भूमिका निभाई थी।

इससे आपको जीआईएस के बड़े कार्य क्षेत्र का अंदाज़ा लग गया होगा। उन तरीक़ों की जानकारी भी हो गयी होगी जिनसे संगठन इसकी क्षमताओं का दोहन करके आम जनजीवन को बेहतर करते हैं। भारत में जीआईएस का संभावित राष्ट्रीय रोल आउट (उदभव) तथा देश के प्राकृतिक व भौतिक साधनों का विशाल डाटाबेस इसकी महत्ता और ज़्यादा बढ़ा देता है।

राष्ट्रीय जीआईएस भारतीय आयोजन प्रक्रिया का मूलभूत अंग होगा। डिवेलपमेंटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी इसकी भूमिका अहम होगी, जिससे शासन के तरीकों में बेहतरी, आयोजन में मदद और आम आदमी का जीवन आसान बनाना आदि चीजें संभव होंगी।

इस इन्फर्मेशन सिस्टम पर सरकारी व निजी क्षेत्र, दोनों की निर्भरता बढ़ने वाली है। इसके लिए उन्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जो जीआईएस के विशेषज्ञ हों, टेक्नोलॉजी का पूर्ण तौर पर उपयोग करने में सक्षम हों ताकि वे इसका पूरा फायदा उठा सकें। स्पष्टतया, इससे उच्च गुणवत्ता वाले जीआईएस प्रोफेशनल व रिसर्च करने वालों की भारी मांग पैदा होगी लेकिन भारत में पेशेवरों में आजकल मौजूद स्किल का स्तर उसे पूरा नहीं कर सकता है। काफी पहले से ही अख़बारों में जीआईएस प्रोफेशनलों की रिक्तियां विज्ञापनों में दिखाई दे रही हैं। जीआईएस सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, डाटा मैनेजर, जीआईएस एनालिस्ट व प्रोजेक्ट मैनेजरों की वैकेंसी आती हैं। बस वे जीआइए एप डेवलप कर सकें, विश्लेषण कर सकें और स्पेशियल डाटासेट से सूचनाएं निकालने में सक्षम हों।

ऑफ बीट

ज्योग्राफिक इन्फार्मेशन सिस्टम्स (जीआईएस) एक नई उभरती इंडस्ट्री है। यह बेहद आकर्षक कैरियर फील्ड है खासकर बीएससी, बीटेक व एमएससी डिग्रीधारी उन विद्यार्थियों के लिए, जो कुछ हट कर करने की ख़्वाहिश रखते हैं। इसमें वेतन भी आईटी जॉब से ज़्यादा है।

इसका रखें ध्यान

आपने परीक्षा, इंटरव्यू आदि तमाम बाधाओं को पार करते हुए अपनी पसंद की नौकरी हासिल कर ली। यह मौक़ा संतुष्ट होकर बैठ जाने का नहीं है, बल्कि आपसे यह अपेक्षा है कि आप पहले ही दिन अपने बॉस व साथियों से अपना लोहा मनवा लें और फिर लगातार स्वयं से सुधार लाते जाएं। अपनी पहली नौकरी में अच्छा काम कर दिखाना सफल कैरियर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको खूब मेहनत करनी होगी। पढ़ाई के दिनों की आदतें छोड़नी होंगी। यह समझना होगा कि अब आप स्टूडेंट नहीं, प्रोफेशनल हैं। ❑❑

इस्लामी दुनिया

ज़िम्मेदार परमाणु शक्ति है पाकिस्तान : आरिफ अल्वी

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने पिछले दिनों कहा है कि उनका देश एक ज़िम्मेदार परमाणु शक्ति है, लेकिन हमला होने पर वह पूरी ताक़त से जवाब देने में नहीं हिचकेगा। साथ ही, उन्होंने अपने देश को आर्थिक रूप से और मज़बूत एवं समृद्ध बनाने का संकल्प दोहराया। अल्वी ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान दिवस परेड को संबोधित करते हुए कहा, 'यह एक महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि हम इस वर्ष पाकिस्तान की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।

सऊदी अरब गठबंधन ने यून में संघर्ष विराम किया

दुबई : यमन की राजधानी सना पर कब्ज़ा करने वाले विद्रोहियों से जूझ रहे सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंध न ने सालों से चले आ रहे युद्ध में एकतरफा संघर्ष विराम शुरू कर दिया हैं हालांकि विद्रोहियों का कहना है कि उन्होंने प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया है। लड़ाई में सऊदी-प्रस्तावित संघर्ष विराम रमज़ान का पवित्र माह की शुरूआत से हुआ है।

इजरायल में गोलीबारी, पुलिस अधिकारी समेत पांच मरे

येरुशलम : इजरायल की राजधानी तेल अवीव के पास गोली में पांच लोगों की मौत हो गई। इजराइल में बीते दिनों में इस तरह का यह तीसरा हमला है, जिसमें कुल 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने बताया, गोलीबारी तेल अवीव के पास बेनी ब्राक में दो अलग-अलग इलाकों में हुई। मारे गए लोगों में एक पुलिस अधिकारी भी शामिल है। फलस्तीनी नागरिक ने वारदात को अंजाम दिया, जिसके मौक़े पर मार गिराया।

सेना प्रमुख से मिलने के बाद टाला संबोधन

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्र के नाम अपने संबोधन को टाल दिया। सेना प्रमुख क़मर जावेद बाजवा और आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के साथ बैठक के बाद उन्होंने यह फैसला किया। राजनयिक सूत्रों ने कहा, बैठक के दौरान बाजवा और अंजुम ने इमरान को राष्ट्र को संबोधित नहीं करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इससे देश में माहौल ख़राब हो सकता है और क़ानून व्यवस्था तहरीक़-ए- इंसाफ़ के नेता फेसल जावेद ख़ान ने संबोधन टाल जाने की आधिकारिक जानकारी दी। हालांकि, संबोधन क्यों टाला गया उसकी जानकारी नहीं दी गई।

महिलाओं के खिलाफ़ अपराध

साझा दर्द, साझी उम्मीदें

नवनीत शर्मा

विशेषण संज्ञा पर हावी हो चले हैं। दलित, अल्पसंख्यक, अश्वेत, पढ़ी लिखी, कटे बालों वाली या हमजिंसी जैसे शब्द स्त्री और स्त्री विमर्श को परिभाषित करने लगे हैं। ये तमाम विभाजनकारी और ग़ैर बराबरी के विशेषण पुरुषों द्वारा पुरुषों की दुनिया के लिए रचे गए, परंतु स्त्री और स्त्री जीवन की सीमाओं को गढ़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्त्रियां इन दमनकारी पाटों में सबसे ज़्यादा पीसी जाती हैं। स्त्री सशक्तिकरण की मुहिम भी स्त्री के लिए न होकर राष्ट्र या समाज की प्रगति के लिए ज़्यादा चिंतित हो जाती है। स्त्री के पढ़ने को परिवार, समाज और देश के लिए आवश्यक क़रार दिया जाता है। शायद परिवार या देश की चिंता न हो तो स्त्री का पढ़ना अभी भी किरकिरी का ही मामला है। स्वतंत्र स्त्री या भिन्न सोचने वाली स्त्री अभी भी हमारे समाज में नाभिकीय अस्त्र के मुक़ाबले अधिक ख़तरनाक मानी जाती है। सिमोन दा बुवार का यह कथन कि 'स्त्रियां पैदा नहीं होती, बल्कि गढ़ी जाती हैं' उस विद्रूप को इंगित करता है जहां ज़नाना क्या है, यह तय करने का विशेषाधिकार पुरुष के पास है।

स्त्रियों के प्रति हिंसा अब सांख्यिकी के दस्तावेज़ बन कर रह गई है। प्रतिक्षण कोई न कोई स्त्री हिंसा काशिकार होती है, चाहे वह गर्भ में हो, गोद में हो, घर में, दफ्तर में, अस्पताल में, वयोवृद्ध हो, कामगार या फिर गृहणी। मानसिक, शारीरिक और यौन हिंसा से अभिशप्त स्त्री अभी भी किसी आंबेडकर की बाट जोह रही है। आधे आसमान और आधी धरती के मालिकान का हक़ और सपना उस हक़ीकत से लांछित है जहां दुनिया भर में तीन से एक स्त्री यौन हिंसा का शिकार है। भारतीय स्त्री की दशा और भी दयनीय है जहां हर घंटे औसतन चार स्त्रियां बलात्कार का शिकार हो रही हैं। इनमें अगर दहेज, मानसिक प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और कन्या भ्रूण हत्या के मामले जोड़ दिए जाएं, तो बासठ प्रतिशत स्त्रियां सांस्थानिक पितृसत्ता के चलते त्रस्त हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 'विकास' और 'प्रगति' के साथ स्त्रियों के प्रति अपराध में सात प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई है। यहां भी विशेषण महत्वपूर्ण हो जाते हैं, दलित स्त्रियों से बलात्कार के मामलों में केवल दो प्रतिशत अपराधियों को दंड मिलता है, जबकि अन्य में यह पच्चीस प्रतिशत है। यह उन आंकड़ों का हवाला है जो रिकॉर्ड हुए, अन्यथा यह लिंग आधारित हिंसा की उस विकराल समस्या के संकेतक मात्र हैं, जिसमें लोक लाज के कारण माना जाता है कि 99 प्रतिशत मामले दर्ज हो ही नहीं पाते। यह हिंसा केवल पुरुष और स्त्री के जैवित स्तर पर भिन्न होने का द्वंद्व न होकर एक सांस्कृतिक विरंचना है, जिसके अनुसार स्त्रियां आंगन और गाय खूंटे में ही सुरक्षित हैं। यह सार्वजनिक 'देशकाल' में स्त्री की स्वतंत्रता को हस्तक्षेप मानने जैसा है। स्त्री को आर्थिक रूप से उत्पादनशील न समझना और न बनने देने का प्रयास है।

स्वतंत्र और सशक्त स्त्री पुरुषों की दुनिया में दख़ल मात्र हैं, सहनीय नहीं है, इसलिए दंडनीय है ताकि उसे अपना स्थान पता रहे। धर्मगत विषयों में भी स्त्री को कोई निर्णय करने संबंधी अधिकार नहीं है हालांकि सारे धार्मिक मूल्यों की संवाहक स्त्री ही है। सारे व्रत, तीज त्यौहार, रस्मो रिवाज़ उसे ही निभाने हैं, परंतु धर्म स्थलों में प्रवेश और अन्तिम संस्कार को लेकर वर्जनाएं हैं। दुनिया के प्रत्येक धर्म में स्त्री को दोयम दर्जे का ही माना गया है। लगभग सभी धर्मों में इस दुनिया के बनने के चरणबद्ध क्रम में स्त्री हर कथोपकथा में हमेशा दूसरे नंबर पर है। जैविक विकास के क्रम में पहले पुरुष आया या स्त्री, यह एक बेमानी सवाल है क्योंकि यहां पहले आना बेहतरी का सूचक नहीं हैं इस क्रम में मानव जाति का प्रादूर्भाव समझा जाता है कि पुरुष और स्त्री एक ही साथ बने होंगे तो हर संदर्भ और प्रसंग में स्त्री का पिछड़ जाना सामाजिक वर्चस्व और संघर्ष की ही गाथा रही होगी।

स्त्री को प्रत्येक काल खंड में बंधक रखने और बंधन में रहने के लिए धर्म सम्मत शास्त्र रचे गए, परंपराएं बनाई गईं और संबंधों के परिमाण में शील और कर्तव्य के दायरे रचे गए। आदर्श स्त्री की परिकल्पना चाहे वैदिक युगीन हो अथवा उत्तर आधुनिक, हमेशा ही पुरुषवादी अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक मूल्यों ने भी स्त्रीत्व को देह धरे का दंड ही माना। इसके लिए फिर उसने विश्व सुंदरी प्रतियोगिताएं आयोजित कीं और स्त्री केन्द्रित साहित्य और सिनेमा को आलोचकों से अनुशंसा तो दिलाई, पर उसे 'मुख्यधारा' से परे ही रखा। विज्ञापनों की दुनिया में भी स्त्री केन्द्र में रही। स्त्री के लिए उपयोगकारी वस्तुओं के विज्ञापनों में भी स्त्री मात्र देह की तरह दर्शायी जाती है।

मानसिक, शारीरिक और यौन हिंसा से अभिशप्त स्त्री अभी भी किसी आंबेडकर की बाट जोह रही है। आधे आसमान और आधी धरती के मालिकान का हक़ और सपना उस हक़ीकत से लांछित है जहां दुनिया भर में तीन से एक स्त्री यौन हिंसा का शिकार है। भारतीय स्त्री की दशा और भी दयनीय है जहां हर घंटे औसतन चार स्त्रियां बलात्कार का शिकार हो रही हैं। इनमें अगर दहेज, मानसिक प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और कन्या भ्रूण हत्या के मामले जोड़ दिए जाएं, तो बासठ प्रतिशत स्त्रियां सांस्थानिक पितृसत्ता के चलते त्रस्त हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 'विकास' और 'प्रगति' के साथ स्त्रियों के प्रति अपराध में सात प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई है।

ऐसे समय में स्त्री की मुक्ति गाथा और स्त्री विशुद्ध स्त्री बने की परिकल्पना बड़ी जीवटता का मामला है। द्वंद्व स्त्री एकता को लेकर इस समाज को और विखंठित करते हैं। दुनियाभर की स्त्रियां एक हो अथवा स्त्रियों दुनिया को एक करो- जैसे नारे अभी भी बड़ी चतुराई से विभाजित कर दिए जाते हैं। आतंकवादी और सिपाही की मां होने के भिन्न सौंदर्यबोध रचे जाते हैं, पुरुष की दुनिया की लड़ाई का ज़िम्मेदार स्त्री को ही बताया जाता है। दलित, अश्वेत, अल्पसंख्यक स्त्रियों के भिन्न अधिकार और कर्तव्य बुने जाते हैं। इन विभाजनों को भले ही स्त्री ने जन्म न दिया हो, इन्हें पोसने और संरक्षण की ज़िम्मेदारी भी स्त्री की ही है। स्त्री के वीरांगना होने का प्रमुख प्रमाण उसके द्वारा वीर पुत्रों को जन्म देना ही हैं। गांधारी और कुंती के चरित्र चित्रण उनके लिए जनमे पुत्रों के आधार पर ही होना तय है। किसकी बेटी, किसकी बहन से लेकर किसकी स्त्री या किसकी मां, यही स्त्री जीवन की समीक्षा की कसौटी है।

इन सब संरचनाओं के विरुद्ध जाकर जिन स्त्रियों ने पुरुषों की दुनिया में दख़ल दिया, अधिकतर को पुरुषों ने खलनायिका समझा या नज़रअंदाज़ किया या अपवाद ही समझा। इसके बावजूद स्त्री ने अपनी संघर्ष यात्रा को जारी रखा। संयुक्त अरब अमीरात की सरा-अल-अमीरी ऐसी ही मिसाल हैं जो इस मुल्क की उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं और जिन्होंने उस पूरी परियोजना का नेतृत्व भी किया जिसने हाल में मंगल गृह पर एक उपग्रह को सफलतापूर्वक पहुंचाया था। जिस वैज्ञानिक समूह ने यह सफलता हासिल की, उसमें अस्सी प्रतिशत स्त्रियां ही हैं। यह समूह अल्पसंख्यक स्त्रियों से संबंधित सभी पूर्वाग्रह खंडित करता हुआ उम्मीद की नई बानगी हैं इसी तरह पैट्रिस कुलर्स, एलिसिया गार्जा और ओपल तोमेती केवल स्त्री, अश्वेत और हमजिंसीयत के संदर्भ में ही मुखर नहीं है बल्कि ग़ैर बराबरी और रंगभेदस जिसकी जड़ें वस्तुत: पितृसत्ता में ही मिलती हैं, को चुनौती देने के लिए 'ब्लैक लाइव्स मैटर' जैसे आंदोलनरूपी संगठन की स्थापना करती हैं। भारतीय स्त्री ने भी जिजीविषा और सम्मानपूर्वक जीवन के लिए याचना न कर, रण का रास्ता चुना। भंवरी देवी से लेकर निर्भया तक सबने अपनी सांस टूटने तक खुद को टूटने से रोका।

अनगिनत गाथाएं भारतीय मानस पटल से लेकर अखबारों तक अपने स्त्री और स्त्रीत्व के गौरव का बखान करती है। कश्मीर की परवीना अहंगर से लेकर केरल की रेहाना फातिमा या गुजरात की जयाबेन देसाई से लेकर नगालैंड की तोखेली कीकोन एक उम्मीद जगाती हैं कि यह दुनिया जब स्त्री विमर्श के अनुरूप रची जाएगी तो समतामूलक होगी, भेदभाव से मुक्त मानवीय होगी। आठ मार्च का इतिहास फरवरी क्रांति और स्त्रियों का आधी के बरक्स पूरी दुनिया पर उनके दावे की याद तो दिलाता ही है, साथ ही पुरुषों को भी कौरव-पांडव से परे जाकर युयुत्सु होना सिखाता है। ❑❑

योगेश कुमार गोयल

उपभोक्ता के हित और क़ानून

केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ज़िला उपभोक्ता अदालतों के क्षेत्राधिकार को नए सिरे से तय किया गया है। केन्द्र ने यह बदलाव उपभोक्ता संरक्षण अधि नियम 2019 के तहत करते हुए उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 अधि सूचित किया है। दरअसल अभी तक ज़िला उपभोक्ता आयोग की एक करोड़ रुपए तक के मामलों की शिकायतों की सुनवाई करने का अधि कार था, जबकि राज्य उपभोक्ता आयोग को एक से दस करोड़ और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में दस करोड़ रुपए से ज़्यादा की शिकायतों की सुनवाई का अधिकार था। नए प्रावधानों के मुताबिक अब जिला आयोग को पचास लाख, राज्य आयोग को पचास लाख से दो करोड़ और राष्ट्रीय आयोग को दो करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाले उत्पादों तथा सेवाओं से संबंधित शिकायतें सुनने का अधिकार होगा। दरअसल केन्द्र का तर्क है कि पुराने नियमों के तहत शिकायतों की सुनवाई की ऊंची सीमा रखे जाने से ज़िला और राज्य स्तरीय उपभोक्ता आयोगों के पास मामले काफी बढ़ गए थे और ये बदलाव उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए किए गए हैं।

वैसे तो बाज़ार में उपभोक्ताओं को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कई क़ानून बनाए गए। लेकिन जब से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अस्तित्व में आया, तब से उपभोक्ताओं को शीघ्र, त्वरित व कम खर्च पर न्याय दिलाने का मार्ग तो प्रशस्त हुआ ही, साथ ही उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की गुणवत्ता में सुधार करने के प्रति सचेत हुए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू होने के बाद भी उपभोक्ता संरक्षण अधि नियम 1986 लागू होने के बाद भी उपभोक्ता अधिकारों को मजबूती प्रदान करने के लिए निरंतर मांग उठती रही है। आख़िरकार 20 जुलाई 2020 को केन्द्र सरकार ने 'उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019' (कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019) लागू किया। संसद ने वर्ष 2019 में ही 'उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019' को मंज़ूरी दे दी थी और नया क़ानून पहले जनवरी 2020 में और फिर बाद में मार्च 2020 में लागू किया जाना तय किया गया।

लेकिन मार्च में कोरोना महामारी की दस्तक और फिर पूर्णबंदी के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। अंतत: 20 जुलाई 2020 को नया उपभोक्ता कानून अस्तित्व में आया और ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए बने नए कानून ने चौंतीस साल पुराने 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986' का स्थान लिया। नए क़ानून के तहत ज़िला उपभोक्ता फोरम में एक करोड़ रुपए तक के मामले, जबकि राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में दस करोड़ रुपए से ऊपर के मामलों की सुनवाई का प्रावधान किया गया। अब नई अधिसूचना के तहत इसी आर्थिक क्षेत्राधिकार को नए सिरे से निर्धारित किया गया है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की ठगी और धोखाधड़ी से बचाने के लिए उपभोक्ता अधिकारों, अनुसूचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों में पूछताछ और जांच करने के लिए उपभोक्ता अदालतों के साथ-साथ एक सलाहकार निकाय के रूप में केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना की व्यवस्था की गई है। नए कानून में खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट करने वाली कंपनियों और भ्रामक विज्ञापनों पर निर्माता तथा विज्ञापन करने वाले जुर्माने और सख़्त सज़ा जैसे प्रावधान भी जोड़े गए हैं। इन प्रावधानों के मुताबिक कंपनी अपने जिस उत्पाद का प्रचार कर रही है, वह वास्तव में उसी गुणवत्ता वाला है या नहीं, इसकी जवाबदेही विज्ञापन करने वाले की भी होगी। भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर उपभोक्ता कानून में सीसीपीए अधिकारों की जांच करने के अलावा वस्तु और सेवाओं को वापस लेने का अधिकार भी होगा।

देशभर में तेज़ी से पांव पसारते ऑनलाइन कारोबार को पहली बार उपभोक्ता कानून के दायरे में लाया गया हैं किसी भी उपभोक्ता की शिकायत मिलने पर अब ई-कारोबारी कंपनी को अड़तालीस घंटे के भीतर उस शिकायत को स्वीकार करना होगा और एक माह के भीतर उसका निस्तारण भी करना होगा। अगर कोई ई-कारोबार कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। यह नियम उन कंपनियों पर भी लागू होगा जो भले ही विदेशों में पंजीकृत हों, लेकिन भारतीय ग्राहकों को सामान और सेवाएं दे रहीं हैं। ई-व्यापार नियमों के तहत ई-कारोबारियों के लिए उत्पाद का मूल्य, उसकी समाप्ति तिथि, उसे लौटाने, पैसे लौटाने, बदलने, वारंटी-गारंटी, वितरण, भुगतान के तरीक़े, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान के तरीकों के बारे में विवरण प्रदर्शित करना जैसे क़दमों को अनिवार्य किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (ई-कॉमर्स) नियमावली 2020 में स्पष्ट व्यवस्था है कि ई-वाणिज्य मंच का परिचालन करने वाली प्रत्येक कंपनी को अपने उपभोक्ताओं के लिए मंच से जुड़े सामान विक्रेताओं द्वारा नियम 6 के उप-नियम 5 के तहत प्राप्त सभी सूचनाओं को प्रमुख स्थान पर दर्शाने की व्यवस्था की जाए। इन नियमों के तहत सरकार द्वारा ई-कॉमर्स मंचों के लिए भारत में शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति किया जाना अनिवार्य है, नोडल अधिकारी की नियुक्ति का नोटिफिकेशन 17 मई 2021 को लागू हो चुका है।

नया उपभोक्ता क़ानून लागू होने के बाद ई-कारोबार कंपनियों के ख़िलाफ़ सामान की गुणवत्ता, पहुंचाने में देरी, सामान बदलने में देरी इत्यादि को लेकर शिकायतों का अंबार लगा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर दर्ज प्रत्येक पांच में से एक शिकायत ई-कारोबारी कंपनियों के ख़िलाफ़ है। राज्यसभा में उपभोक्ता मामलों और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने एक सवाल के जवाब में बताया भी था कि अप्रैल 2019 से नवंबर 2021 के बीच ई-कारोबार कंपनियों के ख़िलाफ़ पांच लाख बार हजार नौ सौ उन्नीस शिकायतें दर्ज की गई। ई-कॉमर्स कंपनियों के ख़िलाफ़ सर्वाधिक चौंसठ हजार नौ सौ चौबीस शिकायतें महाराष्ट्र में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में तिरसठ हजार दो दौ पैंसठ ओर दिल्ली में पचास हजार से ज़्यादा शिकायतें दर्ज हुई। ज्यादातर राज्यों में यह आंकड़ा बीस से तीस हजार का था।

हालांकि नया उपभोक्ता कानून लागू होने के बाद उम्मीद की गई थी कि यह जहां देश के उपभोक्ताओं को और ज़्यादा ताक़तवर बनाएगा, वहीं इसके तहत उपभोक्ता विवादों को समय पर और प्रभावी एवं त्वरित गति से सुलझाने में मदद भी मिलेगी। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्यों के उपभोक्ता संरक्षण आयोगों तथा पंचाटों में ख़ाली पदों को लेकर कड़ी टिप्पणी की, उससे स्पष्ट है कि उपभोक्ता अधिकारों को नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए सरकार को गंभीरता दिखानी होगी। अदालत ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए कहा था कि यदि ये रिक्तियां भरी नहीं जा सकती है तो सरकार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ही रद्द कर देना चाहिए। कई अन्य देशों की तुलना में भारत में उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरुकता अपेक्षित रूप से पहले ही काफी कम है, ऐसे में यदि उपभोक्ता संरक्षण आयोगों और पंचाटों में पद ख़ाली पड़े रहेंगे तो उपभोक्ताओं की शिकायतों पर सुनवाई कब होगी? ऐसी परिस्थितियों में त्वरित न्याय का सपना तो सपना ही बन कर रह जाएगा। ❑❑

उपभोक्ताओं को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कई क़ानून बनाए गए। लेकिन जब से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अस्तित्व में आया, तब से उपभोक्ताओं को शीघ्र, त्वरित व कम खर्च पर न्याय दिलाने का मार्ग तो प्रशस्त हुआ ही, साथ ही उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की गुणवत्ता में सुधार करने के प्रति सचेत हुए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू होने के बाद भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू होने के बाद भी उपभोक्ता अधिकारों को मजबूती प्रदान करने के लिए मांग उठती रही है।

नया उपभोक्ता कानून लागू होने के बाद उम्मीद की गई थी कि यह जहां देश के उपभोक्ताओं को और ज़्यादा ताक़तवर बनाएगा, वहीं इसके तहत उपभोक्ता विवादों को समय पर और प्रभावी एवं त्वरित गति से सुलझाने में मदद भी मिलेगी। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्यों के उपभोक्ता संरक्षण आयोगों तथा पंचाटों में ख़ाली पदों को लेकर कड़ी टिप्पणी की, उससे स्पष्ट है कि उपभोक्ता अधिकारों को नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए सरकार को गंभीरता दिखानी होगी।

ख़ास ख़बरें

मॉस्को पर विश्वास नहीं कर सकते : जेलेंस्की

कीव : यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ जारी वार्ता में कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं, लेकिन मॉस्को पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वहीं, क्रेमलिन ने कहा कि यूक्रेन के साथ वार्ता में कोई सफलता नहीं मिली है। जेलेंस्की ने वीडियो संबोधन में कहा, इस्तांबुल को मॉस्को की प्रतिक्रिया ठीक थी और वार्ता आगे बढ़ने की उम्मीद है।

चीन में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का एक ब्लैक बॉक्स मिला

वुझोउ : चीन में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के दो 'ब्लैक बॉक्स' में से एक मिल गया है। राहतकर्मियों को यह जानकारी दी। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की ख़बर के अनुसार चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के यात्री विमान का एक ब्लैक बॉक्स मिल गया है। चाइना इस्टर्न एयरलाइंस के यून्नान ब्रांच के चेयरमैन सुन शियिंग ने सम्मेलन में बताया था कि दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में सवार 132 लोगों में से कोई अभी तक जीवित नहीं मिला है।

विषाक्त टॉफी खाने से चार बच्चों की मौत

कुशीनगर : उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के कसया क्षेत्र में कथित रूप से विषाक्त टॉफी खाने से एक ही परिवार के तीन मासूमों सहित चार बच्चों की मौत हो गई। उपजिलाधिकारी वरुण कुमार पांडेय ने ग्रामीणों के हवाले से बताया कि कसया थाना क्षेत्र के कुड़वा उर्फ दिलीप नगर के लठउर टोला की मुखिया देवी सुबह घर के दरवाज़े पर झाड़ू लगा रही थीं। इसी दौरान उन्हें एक पॉलिथिन में पांच टॉफी और नौ रुपए मिले। उन्होंने उसमें से तीन टॉफी अपने नातियों और एक टॉफी पड़ोसी के बच्चों को दे दी।

दलित युवक को मंदिर में नाक रगड़ने को किया मजबूर

जयपुर : राजस्थान के अलवर जिले में एक दलित युवक को कुछ लोगों ने मंदिर में कथित रूप से नाक रगड़ने को मजबूर किया तथा उससे मारपीट भी की। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार पीड़ित युवक राजेश कुमार मेघवाल एक निजी बैंक में काम करता है। आरोप हे कि सोशल मीडिया पर फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' की आलोचना संबंधी अपनी एक टिप्पणी के जवाब में उसने हिन्दू देवताओं के लिए कथित तौर पर अपमाजनक टिप्पणी लिखी थी, जिससे नाराज़ कुछ लोगों ने उससे मारपीट की और उसे मंदिर में नाक रगड़ने को मजबूर किया तथा माफ़ी मांगने को कहा।

रमज़ान की आमद

जब आप ये पंक्तियां पढ़ रहे होंगे तब तक रमज़ान का माहे मुबारक अपने पूरे शबाब के साथ हमारे बीच अपना अहसास दिला चुका होगा। इस्लाम का चौथा रुक्न रोज़ा है। हर आक़िल बालिग़, तंदुरुस्त मुकीम मुसलमान पर रमज़ान के रोज़े रखना फर्ज़ हैं जब रमज़ान का महीना आए तो पूरे महीने रोज़ें रखें:-

रोज़ा की क़िस्में

1. फर्ज़: जैसे रमज़ान के रोज़े और कफ्फ़ारे के रोज़े। 2. वाजिब: जैसे नज़्र के रोज़े और इन नफ्ल रोज़ों की कज़ा जिनको तोड़ दिया गया हो। 3. नफ्ल : जैसे मोहर्रम की 9वीं 10वीं, 11वीं तारीख़ के रोज़े जिल हिज्जा के नवीं तारीख का रोज़ा, शाबान की 15वीं तारीख का रोज़ा, शव्वाल के महीने में छह रोज़े, अय्याम बैज़ (हर महीने की 13वीं, 14वीं, 15वीं) तारीख के रोज़े, पीर और जुमेरात के रोज़े। रोज़े के फरायज़ : रोज़े के फराइज़ तीन हैं। 1. नीयत करना, 2. सुबह सादिक़ से गुरूब आफताब तक खाना या पानी या किसी और चीज़ को पेट में न जाने देना। 3. सोहबत न करना।

रोज़े की सुन्नतें पांच हैं। 1. देर से सेहरी करना, 2. अफ्तारी जल्दी करना, 3. क़ुरआन शरीफ़ की तिलावत करना, 4. बेहूदा बातों से बचना, 5. रमज़ानुल मुबारक के आख़िरी अशरा में ऐतकाफ़ करना (आलमगीरी)

वह चीज़ें जिन से रोज़ा फासिद नहीं

1. मिसवाक करना, 2. सिर वगैरह में तेल लगाना, 3. आंखों में दवा या सुरमा डालना, 4. खुश्बू सूंघना, 5. गर्मी या प्यास की वजह से गुस्ल करना या तर (गीला) कपड़ा जिस्म पर रखना, 6. किसी किस्म का इन्जक्शन लगवाना या टीका लगवाना, 7. भूलकर खाना पीना, 8. हलक़ में बिला इख़्तयार धुआं या ग़र्द गुबार (धूल-मिट्टी या मक्खी वगैरहा का दाखिल हो जाना, 9. कान में बिला कसद पानी चले जाना, 10. खुद-बखुद कै (उलटी) आ जाना, 11. सोते हुए अहतलाम (गुस्ल की हाजत) हो जाना, 12. दांतों से खून निकलकर हलक़ में न पहुंचना, 13. अगर ख्वाब में या सोहबत से गुस्ल की ज़रूरत हो गयी और सुबह सादिक़ होने से पहले गुस्ल नहीं किया और इसी हालत में रोज़ा रख लिया तो रोज़े में ख़लल नहीं आया। (मसायल रोज़ा)

मसला:- ईद और बकराईद के दिन और बकराईद के बाद तीन दिन (11, 12, 13 ज़िलहज्जा को रोज़ा रखना हराम है) (दुरे मुख़्तार)

मसला:- रमज़ान शरीफ, नज़्र मुईन और नफ्ली रोज़ों की रात से नीयत करना ज़रूरी नहीं नस्फ उल निहार (दोपहर तक) नीयत कर लेना ठीक है। अलबत्ता रमज़ान वगैरह की क़ज़ा और कफ्फ़ारा के रोज़ों में रात से नीयत करना ज़रूरी है। (शामी)

जिन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है

1. मंजन, कोयला, टूथपेस्थ वगैरह से दांत साफ करना, 2. रोज़ा की हालत में लड़ना झगड़ना या किसी को गाली देना, 3. ग़ीबत करना, 4. बिला गरज़ किसी चीज़ का चखना, 5. मुंह में थूक जमा करके निगल जाना, 6. बीवी के साथ बोस व किनार करना। (मसायल रोज़ा)

मसला:- ऐसी खुश्बू सूंघना जिस में धुआं हो जैसे अगरबत्ती वगैरहा इस से रोज़ा फासिद हो जाता है। (दुरमुअल शामी)

रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें

रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें दो क़िस्म पर हैं : एक वह जिन से सिर्फ कज़ा वाजिब होती है। ❑❑

क्या आप हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैही वसल्लम के बारे में जानते हैं?

नबी सल्लल्लाहो अलैही वसल्लम की पैदाइश का दिन : 12 रबीउल अव्वल (20 अप्रैल 571 ई०)

नबी सल्लल्लाहो अलैही वसल्लम के वालिद/वालिदा का नाम : हज़रत अब्दुल्लाह/हज़रत आमिना

नबी सल्लल्लाहो अलैही वसल्लम के दादा और नाना का नाम : हज़रत अब्दुल मुत्तलिब/हज़रत वहब

नबी सल्लल्लाहो अलैही वसल्लम ने बचपन में हज़रते सुवैबा/हज़रत आमिना/हज़रते हलिमा का दूध पिया।

नबी सल्ल० की बीवियों के नाम जो हर मुसलमान की माँ हैं।:- (1) हज़रत खदीजा, (2) हज़रते सौदह, (3) हज़रते आएशा, (4) हज़रत हफ्सा, (5) हज़रते उम्मे सल्मा, (6) हज़रते उम्मे हबीबा, (7) हज़रत ज़ैनब, (8) ज़ेनब बिन्ते खुज़ेमा, (9) हज़रते मैमुना, (10) हज़रते जुवेरिया, (11) हज़रते सफिया रज़ि०।

नबी सल्ल० के 03 साहबज़ादों के नाम, जिनका विसाल बचपन में हो गया था:-(1) हज़रते क़ासिम, (2) हज़रते इब्राहीम, (3) हज़रते अब्दुल्लाह।

हुज़ूर सल्ल० की चार साहिबज़ादियों के नाम:- (1) हज़रते ज़ेनब, (2) हज़रते रुकय्या, (3) हज़रते उम्मे कुलसूम, (3) हज़रते फातिमा।

हुज़ूर सल्ल० के 12 चचाओं के नाम:- (1) हारिस, (2) अबू तालिब, (3) ज़ुबर, (4) हम्ज़ा, (5) अब्बास, (6) अबू लहब, (7) गैदान, (8) मुकव्विम, (9) ज़िरार, (10) कुसुम, (11) अब्दुल कअब, (12) जहल।

हुज़ूर सल्ल० के 03 नवासों के नाम:- (1) हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम मोहसिन

हुज़ूर सल्ल० के 03 नवासियों के नाम:- (1) हज़रते ज़ैनब, (2) हज़रते उम्मे कुलसुम, (3) हज़रते रुक़य्या (हज़रते मोहसिन व हज़रते रुकय्या का विसाल बचपन में हो गया था)

हुज़ूर सल्ल० की 06 फूफियों के नाम:- (1) हज़रते सफिया, (2) अतिका, (3) उमेमा, (4) उम्मे हकिम, (5) बर्रह, (अरवा)। इनमें सिर्फ हज़रते सफिया ईमान लाई)।

हुज़ूर सल्ल० के खुद्दामे ख़ास के नाम:- (1) हज़रत अनरस, (2) हज़रत रबिआ, (3) हज़रत ऐमन, (4) हज़रत अब्दुल्लाह, (5) हज़रत उक्बा, (6) हज़रत अस्लअ, (7) हज़रत अबुज़र गिफारी, (8) हज़रत हुनैन, (9) हज़रत मुहाजिर मौला, (10) हज़रत नुएम, (11) हज़रत अबुल हमर (12) हज़रत अबुस्समह।

दरबारे नुबूव्वत के ख़ास नात ख़्वा के नाम:- (1) हज़रते क़अब बिन मालिक, (2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा, (3) हज़रत हस्सान।

हुज़ूर के खुसूसी 04 मुअज़्ज़िन के नाम:- (1) हज़रते बिलाल, (2) हज़रत अब्दुल्लाह, (3) हज़. सअद बिन आएद, (4) हज़रते अबू महज़ुरा।

हुज़ूर सल्ल० के दामादों के नाम:- (1) हज़रत अबूल आस, (2) हज़रत उस्मान ग़नी, (3) हज़रत अली शेरे ख़ुदा।

हुज़ूर सल्ल० के ससूर के नाम (जिनकी बेटियों से आपने निकाह किया)।

(1) खुवेल्दा बिन असद, (2)जमआ, (3) हज़रत अबू बकर सिद्दिक, (4) हज़रत उमर फारूक़, (5) हुज़ैफा, (6) अबू सुफियान, (7) हारिस, (8) हारिस बिन ज़रार, (9) हुय्यि बिन अख़तब।

हुज़ूर सल्ल० ने किन सहाबी को कौन सी मस्जिद जलाने का हुक्म दिया।

मस्जिदे ज़रार (जो मुनाफिक़ों ने) मुसलमानों को गुमराह करने के लिए बनाई।

हज़रते मालिक (हज़रते मअन को मस्जिदे ज़रार को जलाने का हुक्म दिया था) इस बारे में सूरह तौबा आयत 107 में आया है।) ❑❑

नूरे क़ुरआन

(सूरा अल बकरह नं० 02)

अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

इस सूरा के प्रारंभ से यहां तक तीन प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया गया, 1. प्रथम मोमिनों का, 2. इनकारियों का जिन के दिलों पर सील कर दी कि वे कदापि ईमान न लायेंगे, 3. तीसरे मुनाफिक़ों का जो देखने में मुसलमान हैं मगर दिल उनका एक ओर नहीं।

ऐ लोगों अपने पालनहार की उपासना करो जिसने तुमको पैदा किया और उन लोगों को भी जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, वह पालनहार ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतारा फिर उससे तुम्हारे खाने के लिए मेवे निकाले सो किसी को अल्लाह के मुक़ाबिल न ठहराओ और तुम तो जानते बूझते हो।

अब सब बन्दों को चाहे ईमान वाले हों या इंकारी हों या मुनाफिक़ संबोधित करके एकेश्वरवाद की शिक्षा दी जाती है, जो ईमान की वास्तविक नींव है। मतलब यह है कि अल्लाह ने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया और वे वस्तुएं बनाई जिनसे तुमको लाभ होता है और आवश्यकता की पूर्ति होती है फिर कितनी मूर्खता है कि तुम उसको छोड़कर किसी दूसरे को उपास्य बनाओ, जो तुमको न लाभ पहुंचा सकता है न हानि, जबकि तुम जानते हो कि उस जैसा कोई नहीं।

और यदि तुम उस कलाम (क़ुरआन) पर जो हमने अपने बंदे पर उतारा है, शंका करते हो तो इस जैसी एक (ही) सूरा ले आओ।

यह बात आ चुकी है कि इस कलाम पाक में शंका का कारण या तो यह हो सकता था कि इस कलाम ही में कोई खटके की बात हो इसलिए उसको दूर करने के लिए इसमें कोई शंका नहीं कहा जा चुका है। या शंका का कारण यह हो सकता है कि किसी के दिल में अपनी समझ में शराबी या शत्रुता के कारण शंका उत्पन्न हो, तो यह दशा चूंकि विद्यमान थी, तो उसको दूर करने का अच्छा ओर आसान तरीक़ा बयान कर दिया कि यदि तुम को इस कलाम के इंसानी कलाम होने का विचार है तो तुम भी एक सूरा ऐसे गुणों से भरी हुई, अपनी आयतों जितनी बनाकर देखो, जबकि तुम साहित्य की योग्यता रखने पर भी नहीं बना सकते, तो समझ लो कि यह अल्लाह का कलाम है, बन्दे का नहीं। इस आयत में आपके रसूल होने की दलील भी आ गयी है।

और अल्लाह के अतिरिक्त जो तुम्हारा सहायक हो उसको बुला लो यदि तुम सच्चे हो।

अर्थात् यदि तुम अपने इस दावे में सच्चे हो कि यह बन्दे का कलाम है तो जितने योग्य कवि और लेखक हैं, अल्लाह के अतिरिक्त उन सबसे मदद लेकर ही एक छोटी सी सूरा ऐसी बना लाओ। या यह मतलब है कि अल्लाह के अतिरिक्त तुम्हारे जितने उपास्य हैं सबसे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करो कि वे इस मुश्किल में मुश्किल में कुछ सहायता करें।

फिर यदि ऐसा न कर सको और कदापि न कर सकोगे तो फिर उस आग से बचो जिस का ईंधन आदमी और पत्थर हैं जो इनकारियों के लिए तैयार हुई रखी है।

फिर इस पर भी अगर तुम ऐसी एक छोटी सी सूरा न बना सको और यह बात विश्वसनीय है कि कदापि न बना सकोगे तो दोज़ख़ की उस आग से डरो जो सब आगों से तेज़ है। उसका ईंधन एकेश्वरवाद के इनकारी इंसान और वे पत्थर हैं जिनकी तुम पूजा करते हो और बचने की तरकीब (उपाय) यही है कि अल्लाह की किताब पर ईमान लाओ। वह आग उन इंकारियों के लिए तैयार की हुई रखी है जो क़ुरआन शरीफ़ और अल्लाह के रसूल सल्ल० को झूठा बताते हैं।

और जो उन लोगों को जो ईमान लाये और अच्छे कार्य किये शुभसूचना दीजिए कि उनके लिए ऐसे बाग़ हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं जब उनको वहां का कोई फल खाने को मिलेगा तो कहेंगे यह तो वहीं है जो हमको इससे पहले मिला था और उनको एक जैसे फल दिये जाएंगे।

जन्नत के फल रंग रूप (शकल सूरत) में दुनिया के मेवों से मिलते-जुलते होंगे मगर स्वाद में जमीन आसमान का अंतर होगा। या यह मतलब है कि जन्नत के मेवे आपस में एक रंग के होंगे और स्वाद अलग-अलग होगा। जब किसी फल को देखेंगे तो कहेंगे, वही किस्म है जो पहले दुनिया में या जन्नत में खा चुके हें और चखेंगे तो स्वाद कुछ अन्य ही पायेंगे।

कांशीराम की मेहनत पर पानी फेरती मायावती

उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों का दौर-दौरा सम्पन्न हो चुका है। जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों में 2017 की तुलना में 57 सीटें कम आने के बावजूद सत्ता में वापस आ गयी वहीं समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते व अपने मत प्रतिशत में भी इजाफा करते हुए, 2017 के मुक़ाबले लगभग 64 सीटें अधिक हासिल कर कुल 111 सीटों पर विजयी होने के बावजूद सत्ता के जादुई आंकड़े से काफी दूर रह गई।

परन्तु इन चुनावों में सबसे अधिक नुकसान बहुजन समाज पार्टी को उठाना पड़ा जिसे 2017 के मुकाबले 18 सीटें और गंवाकर राज्य की मात्र एक सीट पर ही जीत हासिल हुई और उस एकमात्र विजयी प्रत्याशी उमाशंकर सिंह के विषय में भी यही बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने निजी जनाधार व लोकप्रियता के चलते यह जीत हासिल की है न कि मायावती के सर्मीन अथवा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के नाते। उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के अंतर्गत रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से विजयी बसपा से निर्वाचित एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह इससे पूर्व भी 2012 व 2017 में यहां से विधायक रह चुके हैं। क्षेत्र में समाजसेवी के साथ-साथ उनकी रोबिनहुड जैसी छवि बनी हुई है। यही उनकी जीत का प्रमुख कारण माना जा रहा है।

प्रश्न यह है कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रहने वाली मायावती के नेतृत्व में ऐसी क्या कमी रह गयी कि जो मायावती अपनी पार्टी के जनाधार की बदौलत देश के प्रधानमंत्री बनने तक के सपने संजोने लगी थीं आज उनकी वही बसपा मृत प्राय सा राजनैतिक दल क्यों प्रतीत होने लगा है? ग़ौरतलब है कि 1984 में कांशीराम ने देश में 85 बनाम 15 प्रतिशत के इसी फार्मूले ने उनकी पार्टी को आसमान पर पहुंचा दिया था। कांशीराम जीवनभर अपनी इसी सामाजिक गणित के प्रति कटिबद्ध रहे और सत्ता के लिये उन्होंने अपने इस सामाजिक अंकगणित की कभी बलि नहीं चढ़ाई। कांशीराम ने 2001 में सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर कुमारी मायावती ने अपना उत्तराधिकारी तो ज़रूर बनाया परंतु 2006 में कांशीराम के देहांत के बाद मायावती ने न केवल बसपा संगठन पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया बल्कि मात्र सत्ता के लिए मनमाने तरीके से कई बार पार्टी की नीतियों व सिद्धांतों से भी समझौता किया। यहां तक कि वे कई बार अपने मुख्य नारों को यू टर्न देते हुये अपनी पार्टी की मूल विचारधारा से समझौता करती भी नज़र आई।

बहुजन समाज के साथ-साथ मायावती ने सर्वजन समाज की बात भी करनी शुरू कर दी। दलित समाज के मतों पर अपना एकाधिकार समझने के बाद मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन करने शुरू कर दिये। भरी सभा में वह जिसे गलियां देते व अपमानित करते फिरती थीं उसी समाज को आकर्षित करने के लिए उन्होंने पार्टी व कांशीराम के सिद्धांतों की बलि चढ़ा दी और इसी भ्रमित करने वाली राजनीति का नतीजा यह निकला कि ताजातरीन विधान सभा चुनावों में मायावती की हालत 'न खुदा ही मिलना न विसाल-ए- सनम, न इधर के रहे न उधर के हुए' जैसी हो गयी।

न ही उन्हें 85 प्रतिशत समाज वाले पारंपरिक वोट मिले न ही 15 प्रतिशत समाज के वह मत हासिल हुए जो पहले भी कभी नहीं मिला करते थे परंतु मायावती ने अपनी इस ऐतिहासिक हार का ठीकरा दलितों या ब्राह्मणों पर नहीं बल्कि मुसलमानों के सिर पर फोड़ा। जबकि मायावती ने मुस्लिम मतों के लिये ब्राह्मण सम्मेलनों की तरह न तो कोई मुस्लिम सम्मेलन आयोजित किये न ही वे कभी मुसलमानों के दुख-दर्द की साथी बनती दिखाई दीं। इसके बावजूद उनका गुस्सा राज्य के मुस्लिम मतदाताओं पर फूटना उनकी राजनैतिक अदूरदर्शिता के साथ-साथ किसी प्रायोजित व नियोजित साज़िश का भी षड्यंत्र नजर आता है। वैसे भी मायावती की तानाशाही व अहंकारपूर्ण कार्यशैली ने भी पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया है। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भले ही स्वप्रशंसा करने अपनी पीठ थपथपाने तथा स्वयं को महामानव प्रदर्शित करने वाले नेता के रूप में जाना जाता हो परंतु मायावती भी मोदी से किसी कीमत पर कम नहीं हैं।

वे लिखित वक्तव्य भी इसीलिये पढ़ती है ताकि उनके मुंह से अनाप शनाप व निकल जाये। याद कीजिये जब मायावती ने स्वयं को दलितों की ज़िन्दा देवी होने का दावा करते हुये अपने समर्थकों से उन पर चढ़ावा चढ़ाने का आह्वान किया था। उत्तर प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मायावती ने गौतम बुद्ध, रविदास, नारायण गुरु, ज्योतिराव फूले, साहूजी महाराज, पेरियार रामासामा, भीमराव अंबेडकर, बसपा संस्थापक कांशीराम के अतिरिक्त स्वयं की भी अनेक मूर्तियों का निर्माण कराया। उनका अपने जीवन काल में ही मूर्तियां स्थापित करने जैसा नया चलन काफी विवादित भी हुआ था। मायावती ने अपनी पार्टी के चुनाव निशान हाथी की भी नोएडा से लेकर लखनऊ तक अनेक विशाल मूर्तियां बनवा डालीं। मायावती जब भी सार्वजनिक रूप से प्रकट होती तो हमेशा एक बड़े सोहफे पर अकेले ही बैठी नज़र आती हैं। कोई नेता उनके साथ या बराबर बैठने का साहस नहीं कर सकता। इस तरह का अहंकारपूर्ण प्रदर्शन तो कभी इंदिरा गांधी जैसी विश्व की महान नेता ने भी नहीं किया।

गत दिनों जब मायावती अपनी पार्टी की ऐतिहासिक हार के बाद मीडिया के समक्ष आई और मुसलमानों को कोसने लगीं उसके बाद चूंकि वे व उनकी पार्टी विवादों में घिर गयी थी और उनके पास इस मुस्लिम विरोधी वक्तव्य देने का कोई स्पष्टीकरण नहीं था इसीलिये उन्होंने अपने पार्टी प्रवक्ताओं को प्रेस कांफ्रेंस करने या टीवी डिबेट में जाने से मना कर दिया। इस बार के चुनाव में भी उनकी भूमिका भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने वाली ही रही। चुनावी विश्लेषकों के अनुसार गत दिनों उत्तर प्रदेश में सम्पन्न हुए चुनावों में मायावती की बसपा तथा ओवैसी की एआईएमआईएम, इन दोनों ही दलों ने सत्ता विरोधी मतों को विभाजित कर भाजपा की मदद ही की है। और शायद मायावती की इसी भ्रमपूर्ण राजनीति के चलते अब तो यह भी कहा जाने लगा है कि यह बसपा का पतन काल है और यदि यह सच है प्रश्न यह है कि क्या मायावती की राजनैतिक कार्यशैली व उनके फैसले कांशीराम की मेहनत पर पानी फेर देंगे? ❑❑

उ.प्र. : योगी ने किया विभाग का बंटवारा गृह समेत 25 विभाग अपने पास रखे

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नीत सरकार के मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया। मुख्यमंत्री योगी ने गृह, आवास एवं शहरी नियोजन, नियुक्ति, कार्मिक, राजस्व सहित 25 महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं। सरकारी प्रवक्ता द्वारा जारी बयान के अनुसार, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम्य विकास एवं समग्र विकास तथा अभियंत्रण, खाद्य उद्यम तथा राष्ट्रीय एकीकरण विभाग दिया गया है। बयान के अनुसार, राज्य के दूसरे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग की ज़िम्मेदारी मिली है।

उसमें कहा गया है कि वरिष्ठ नेता सुरेश खन्ना को वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री विभाग की ज़िम्मेदारी मिली है जबकि सूर्य प्रताप शाही को कृषि, कृषि एवं अनुसंधान विभाग मिला है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग की ज़िम्मेदारी मिली है। प्रवक्ता के मुताबिक, बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, नंन्द गोपाल नंदी को औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई तथा निवेश प्रोत्साहन विभाग मिला है।

मंत्रियों को मिले विभागों की सूचि

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ:- गृह नियुक्ति, कार्मिक, सतर्कता, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य एवं सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, भूतत्व एवं प्रशासन, गोपन, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य सम्पत्ति, उप पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, अवस्थापना, भाषा, अभाव सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबंधन, किराया नियंत्रण, प्रोटोकॉल, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल, नागरिक उड्डयन, न्याय एवं विधायी विभाग।

कैबिनेट मंत्री

सुरेख खन्ना: वित्त एवं संसदीय कार्य।
सूर्य प्रताप शाही: कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान।
स्वतंत्र देव सिंह: जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण।
बेबी रानी मौर्य: महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार।
लक्ष्मी नारायण चौधरी: गन्ना विकास एवं चीनी मिलें।
धर्मपपाल सिंह: पशुधन एवं विकास, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक़्फ एवं हज तथा नागरिक सुरक्षा
नंद गोपाल नंदी: औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई तथा निवेश प्रोत्साहन।
भूपेन्द्र चौधरी: पंचायती राज।
अनिल राजभर: श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय।
जितिन प्रसाद: लोक निर्माण।
राकेश सचान: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग।
अरविंद कुमार शर्मा: नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोज़गार एवं ग़रीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत।
योगेन्द्र उपाध्याय: उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी।
आशीष पटेल: प्रविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप।
संजय निषाद: मत्स्य।

राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार

नितिन अग्रवाल: आबकारी और मद्य निषेध।
कपिल देव अग्रवाल: व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास।
रवीन्द्र जायसवाल: स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन।
संदीप सिंह: बेसिक शिक्षा।
गुलाब देवी: माध्यम शिक्षा।
गिरीश चंद यादव: खेल एवं युवा कल्याण।
धर्मवीर प्रजापति: कारागार एवं होमगार्ड।
असीम अरुण: समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति।
जयंत प्रताप सिंह राठौर: सहकारिता।
दया शंकर सिंह: परिवहन।
नरेन्द्र कश्यप: पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण।
दिनेश प्रताप सिंह: उद्यान कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात।
अरुण कुमार सक्सेना: वन एवं पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन।
दयाशंकर मिश्र (दयालु): आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन।

राज्यमंत्री

मयंकेश्वर सिंह: संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण।
दिनेश खटीक: जल शक्ति।
संजीव गोंड: समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण।
बलदेव सिंह औलख: कृषि, कृषि शिक्षा तथा कृषि अनुसंधान
अजीत पाल: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक्स तथाा सूचना प्रौद्योगिकी

बाक़ी पेज 11 पर

भारतीय बैडमिंटन का नया लक्ष्य

बैडमिंटन खिलाड़ियों का जो प्रतिनिधिमंडल तीन देशों के दौरे पर यूरोप जा रहा है, उसमें से इस बार राष्ट्र का ध्यान 20 वर्षीय कुमाऊंनी युवा लक्ष्य सेन पर होगा, जो प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद का अनुकरण करते हैं। ग़ौरतलब है कि प्रकाश पादुकोण ने 1980 और पुलेला गोपीचंद ने 2000 में ऑल इंग्लैंड की प्रतिष्ठित ट्रॉफी पर कब्ज़ा जमाया था।

लक्ष्य के मुख्य कोच विमल कुमार को, जिन्होंने साइना नेहवाल को नंबर एक रैंकिंग तक पहुंचाया था, विश्वास है कि लक्ष्य बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। विमल कहते हैं कि 'लक्ष्य के पास तेज़ बैडमिंटन दिमाग़ है। वह जानते हैं कि कब स्ट्राइक करना है, कितना हमला करना है, कब पीछे हटना है और कब इंतज़ार करना है। उनके रक्षण में सभी स्तरों पर सुधार हुआ है और उनका आक्रमण तेज़ व मिश्रित है। अभी कोरियाई कोच यू यंग सू लक्ष्य को गति के मानक पर परख रहे हैं। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता यू यंग सू को प्रकाश पादुकोण अकादमी ने 2024 के पेरिस ओलंपिक तक कोच बनाए रखने का फैसला किया है।

लक्ष्य के बारे में अच्छी बात यह है कि वह कभी नेट पर अपने प्रतिद्वंद्वी से डरते नहीं। लक्ष्य कहते हैं 'मैंने दुनिया के मौजूदा नंबर एक विक्टर एक्सेलसन को छोड़कर दुनिया के सभी शीर्ष एकल खिलाड़ियों को हराया हैं लेकिन मैं वहां पहुंच रहा हूं और अब मेरे पास उनकी सभी चालों का जवाब देना चाहिए। विक्टर के ख़िलाफ़ चार मैचों में लक्ष्य को लगभग एकतरफा हार मिली। लक्ष्य हार नहीं मानते। पिछले वर्ष विक्टर के ख़िलाफ़ एक मैच में स्कोर 12-2-/4-13 था, लेकिन तयशुदा हार के बावजूद लक्ष्य ने अंत तक पूरी मेहनत से से मुक़ाबला किया। ऐसे ही, शीर्ष चीनी खिलाड़ी झोउ पेंग के ख़िलाफ विश्व चैम्पियनशिप के क्वार्टर फाइनल में झोउ को चकमा देते हुए लक्ष्य ने हार के जबड़े से जीत छीन ली।

जनवरी में इंडिया ओपन के फाइनल में विश्व चैम्पियन लोह कीन यू को दो मैचों में सीधे हराकर लक्ष्य ने अपने प्रदर्शन का स्तर ऊंचा कर लिया है। हालांकि विमल कुमार का कहना है कि हमें उस पर ज़्यादा ओपन लक्ष्य के लिए अभ्यास मैच जैसा होगा, क्योंकि यदि वह विक्टर को हरा देते हैं, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ बर्मिंघम में उतरेंगे।

लक्ष्य के पास ऑल इंग्लैंड में पहले दो मैच मुश्किल हैं। उनके पास पहले दौर में हमवतन सौरभ वर्मा है, जबकि प्री क्वार्टर फाइनल में उनका मुक़ाबला तीसरी वरीयता प्राप्त एंटोनसेन या लोह कीन यू से होना चाहिए। मेरा मानना है कि इन्हें हराकर अगले राउंड में वह दो बार के विश्व चैम्पियन केंटो मोमोटा से भिडेंगे। यही वह जगह होगी, जहां उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में होना होगा।

मोमोटा के ख़िलाफ़ जीत का मतलब है फाइनल में विक्टर के साथ टकराव, जब पूरा देश वह मैच देखने टीवी से चिपककर बेठैगा। लंबे खिलाड़ी नेट प्ले में हमेशा कमज़ोर होते हैं और यही वह जगह है, जिस पर विमल कुमार यंग सू और प्रकाश पादुकोण लक्ष्य को ध्यान सबसे अधिक केन्द्रित करेंगे। संयोग से लक्ष्य आज नेट प्ले के मामले में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं ऑल इंग्लैंड अच्छा प्रदर्शन उन्हें आगे बढ़ाएगा। प्रकाश पादुकोण ने पिछले वर्ष मुंबई में एक प्रेस वार्ता में कहा था कि आप हज़ार खिताब जीत लें, लेकिन अगर ऑल इंग्लैंड या विश्व

बाक़ी पेज 11 पर

खेल में चोट का साथ हमेशा रहता ही है: अक्षर

सवाल:- चोट आपको बहुत परेशान कर रही है?

जवाब:- (हंसते हुए) वो तो पता नहीं, शनि, राहु, केतू कौन कहां मेरी कुंडली में बैठा हुआ है, लेकिन चोट खिलाड़ी के जीवन का हिस्सा है। आपको चोट लगती रहती है, मैदान पर भी लगती रहती है।

सवाल:- चोट तो शरीर पर लगती है, लेकिन दिमाग़ में भी कुछ रहता होगा?

जवाब:- चोट आपके हाथ में नहीं होती तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। निश्चित रूप से मानसिक तौर पर थोड़ा दबाव आ जाता है कि अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर वही बात कि आप अपने आप को मानसिक रूप से कैसे देखते हो। ऐसे समय में मैं वह करता हूं जो मुझे ज़्यादा पसंद होता है। मैं दोस्तों के साथ घूमा हूं और अपने को व्यस्त रखता है।

सवाल:- क्या-क्या चोटिल हो चुका है.?

जवाब:- अब मेरी नाक, दायां अंगूठा, बायीं अनामिका अंगुली, पिंडली, घुटना चोटिल हो चुका हे, मतलब सिर से लेकर पैर तक कुछ न कुछ चोटिल हो चुका है वो कहते हैं न दाग़ अच्छे हैं, तो शरीर में मैंने सब जगह दाग छोड़ दिए हैं। अब लग रहा है कि ये दाग़ अच्छे रहेंगे। उम्मीद यही है कि अब लंबे समय तक कोई चोट नहीं लगे।

सवाल:- लोग सोचते हैं कि क्रिकेट आसान हैं, लेकिन यहां काफी चोट लगती है.?

जवाब:- वो तो है ही, बाहर बैठे तो सबको लगता है कि ये फाइव स्टार में बैठे खाना खा रहे हैं, विदेश में घूम रहे हैं, इन्हें ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। वो तो ये सब जानता है इन्हें ही पता है कि कितनी मेहनत लगती है, इतनी आसानी से कुछ मिलता नहीं है।

सवाल:- चोट के कारण आपको टीम इंडिया से बाहर होना पड़ा। फिर दिल्ली कैपिटल्स में अच्छा प्रदर्शन करके टीम इंडिया में जगह बनाई?

जवाब:- मेरा जब भारत के लिए पर्दापण हुआ था तो वह आइपीएल के कारण ही हुआ था और उसके बाद जब जब मैं चोटिल हुआ। उसके बाद मुझे मौक़ा मिला तो बड़े मंचों में आइपीएल ही है, इंडिया-ए भी है, लेकिन इंडिया-ए में इतने मैच नहीं होते। आइपीएल एक लंबा प्रारूप होता है, आपको 14 मैच मिलते हैं और आप लगातार प्रदर्शन करते हैं तो सभी की नज़र में आते हैं।

सवाल:- लोगों को लगता है कि आपकी गेंद ज़्यादा स्पिन नहीं होती है लेकिन आप ब्रेक-थ्रू दिला देते हैं..?

जवाब:- निश्चित रूप से मुझे अपनी गेंदबाज़ी के बारे में पता है और में जानता हूं कि मेरी क्या ताक़त है और क्या कमज़ोरी हैं मैं अपनी ताक़त पर गेंदबाज़ी करता हू। ❑❑

आर्थइटिस के उपचार के अनेक तरीके

आर्थइटिस के उपचार में फिजिकल थैरेपी और ऑक्युपेशनल थैरेपी बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थाईटिस के कारण मरीज़ों को अक्सर जोड़ों में अकड़न महसूस होती है। इसका मुख्य कारण है जोड़ों से बिल्कुल ही काम न लेना। हालांकि जोड़ों से काम लेने में दर्द होता है और इन पर ज़्यादा जोर पड़ने से ये और भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं लेकिन इनसे बिल्कुल ही न चलाने से दर्द और बढ़ सकता है क्योंकि ऐसे में ये अकड़ने लगते हैं इसलिए आर्थ्राइटिस के मरीजों के लिए फिजियो थैरेपी बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। मरीज फिजिकल थैरेपिस्ट से जोड़ों को क्षति पहुंचाए बिना अकड़न दूर करने के तरीके सीख सकते हैं। फिजिकल थैरेपी चोट लगने, जोड़ों की सर्जरी और कृत्रिम ज्वाइंट रीप्लेसमेंट सर्जरी के मरीज़ों के लिए भी मददगार होती है। ओस्टियोआर्थाइटिस के दर्द और अकड़न में राहत के लिए कई दवाएं और उपचार उपलब्ध हैं लेकिन गंभीर रूप से प्रभावित मरीज़ों के लिए ज्वाइंट रीप्लेसमेंट सर्जरी का विकल्प भी है।

ऑक्युपेशनल थैरेपी

रोज़मर्रा के काम करते हुए जोड़ों पर दबाव पड़ता है जो दर्द और क्षति का कारण बन जाता है। इस वजह से मरीज़ का जीवन प्रभावित होने लगता है। इससे बचने के लिए ऑक्युपेशनल थैरेपी मददगार होती है। आक्युपेशनल थैरेपिस्ट आपको बताते हैं कि घर और ऑफिस में किस तरह के परिवर्तन करने चाहिए ताकि जोड़ों पर कम से कम दबाव पड़े। काम करने की सही तकनीक बताने के अलावा वे कुछ सहायक उपकरण भी दे सकते हैं ताकि आपका काम आसान हो सके। हाथों और कलाई के लिए वे आपको स्प्लिंट दे सकते हैं। इसी तरह गाड़ी चलाने, नहाने, तैयार होने और घर के कामों को आसान बनाने के लिए भी ज़रूरत के अनुसार उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

फिजिकल थैरेपी

फिजियोथैरेपी का उद्देश्य होता है कि मरीज़ की हालत में इतना सुधार हो जाए कि मरीज़ अपने सभी साधारण कार्य बिना किसी परेशानी के खुद कर सके। दूसरों पर निर्भरता कम होने से मरीज़ का आत्मविश्वास बना रहता है। दैनिक जीवन के कार्य करने के लिए जोड़ का मूवमेंट बना रहना बहुत महत्वपूर्ण है। फिजियोथैरेपी इसी दिशा में काम करती है। जोड़ से काम न लेने पर उनमें दर्द और अकड़न बढ़ने के साथ ही आसपास की मांसपेशियां कमज़ोर भी पड़ने लगती हैं। फिजियाथैरेपी से मांसपेशियां मज़बूत होती है जिससे कमज़ोर जोड़ को सहारा मिलता है।

फायदे

मरीज़ को उसकी बीमारी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती है जिससे वो इसका प्रबंध बेहतर ढंग से कर सकता है।

वजन अधिक होने से जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। वज़न कम करने के लिए डायट प्लान की जा सकती है। आर्थ्राइटिस के लिए कोई विशेष डायट तो निर्धारित नहीं की जाती है लेकिन वजन घटाने के लिए प्लान की गई डाइट ही आर्थ्राइटिस रोगियों के लिए सबसे मुफीद होती है।

मरीज़ को सही फुटवेयर चुनने के बारे में बताया जाताा है। फुटवियर सही आकार और साइज के होना चाहिए। जूतों के बाहरी तले पर शॉक एब्जार्बर होने चाहिए ताकि जोड़ों पर झटका न पड़े।

बेड रेस्ट करने से जोड़ों का दर्द और सूजन दोनों कम होती है। खासकर एक से अधिक जोड़ प्रभावित होने पर मरीज़ों में थकान होना मुख्य समस्या होती है। प्रभावित जोड़ों को पूरा आराम मिलने से बहुत राहत मिलती है। मरीज़ के लिए विशेष रूप स्पिलिंट बनाए जा सकते हैं।

सेक करने से दर्द में राहत मिलती है। चिकित्सक की सलाह के अनुसार ठंडे और गर्म पैक से सैक किया जा सकता है। इससे जोड़ों की अकड़न और मांसपेशियों की सूजन कम होती है। व्यायाम के पहले जोड़ों पर गर्म पानी डालकर सेक करने से व्यायाम करने में आसानी होती है।

व्यायाम आर्थ्राइटिस के उपचार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रोज़ाना सही तरीके से करने पर यह बहुत प्रभावी होता है। यह कुशल प्रशिक्षक की देख रेख में करना चाहिए ताकि ग़लती की आशंका न रहे।

ये करें

चिकित्सक की सलाह पर नियमित व्यायाम करें। सप्ताह में 3-4 दिन सुबह या शाम को 30-40 मिनट तक पैदल चलें।

नियमित अंतराल से वजन चेक करवाते रहे।

जमीन पर रखी कोई भी चीज़ उठाने के लिए झुकते समय अपनी कमर सीधी रखकर घुटनों को मोड़ें।

ये न करें

पालती लगाकर बैठने से बचें।

भारी वज़न उठाने से बचें।

लंबे समय तक एक प्रकार के काम करने से बचें। इससे जोड़ों पर दबाव बढ़ता है (जैसे लंबे समय तक एक ही स्थिति मे बैठे रहना या बहुत देर तक खड़े रहना)।

उन कामों से बचें जिनसे जोड़ों पर झटका पड़ता हो।

ठण्डे मौसम में व्यायाम करने से बचें। ❑❑

शेष... भारत के क़सीदे क्यों पढ़ रहे हैं...

रिश्ते बनाने की ख़्वाहिश रही है लेकिन वह फौज को नाराज़ नहीं कर पाता क्योंकि उसी की मेहरबानी से प्रधानमंत्री बनता है और पाकिस्तानी फौज का अस्तित्व भारत से नफ़रत और दुश्मनी की बुनियाद पर ही टिका है। अन्यथा वहां की अवाज तो आज भी हिन्दुस्तान से भाईचारा चाहती है। भले ही इमरान ख़ान अपने स्वार्थ की ख़ातिर भारत की तारीफ करने पर विवश हुए हों, लेकिन सच है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए दुनियाभर के दरवाज़ों पर नाक रगड़ी है।

विभाजन के बाद पाकिस्तान ने कुछ वर्ष पश्चिम एशिया के इस्लामी देशों और राष्ट्रमंडल देशों के दर पर कश्मीर की भीख मांगी। फिर 1954 के बाद आठ वर्ष वह अमेरिका से कश्मीर की गुहार लगाता रहा। नाकाम रहा तो चीन और इंडोनेशिया की शरण में गया। इसके बाद 1964 में रूस के द्वार जा पहुंचा। फिर अमेरिका की गोद में जा बैठा लेकिन अमेरिका उसे झुनझुना दिखाता रहा। इसके बाद पाकिस्तान फिर चीन और इस्लामी देशों की शरण में है। अर्थात् जहां से सफर शुरू किया था, उसी बिन्दु पर पाकिस्तान खड़ा है। वह कहते हैं कि ऐसा कोई गठबंधन नहीं बचा, जिसके द्वार पाकिस्तान न गया हो। वह उस देश से दोस्ती क्यों नहीं करता, जिसकी दुश्मनी की ख़ातिर उसे दर-दर भटकना पड़ रहा है। क्या पाकिस्तान अब असली सबक़ सीख रहा है।❑❑

शेष... एनडीए सरकार को....

मूलरूप से भाजपा के थे।

सवालः- बिहार का चुनाव आप लोग क़ानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर लड़े थे लेकिन इस दिशा में बहुत ठोस होता हुआ दिखा नहीं है?

जवाबः- मैं बिहार सरकार का उद्योग मंत्री हूं। दावे के साथ यह कह सकता हूं कि बिहार में जितना निवेश हुआ है, वह पहले कभी नहीं हुआ। करीब 40 हज़ार करोड़ का निवेश आया है। केन्द्र से भी बिहार को मेगा फूड पार्क मिला हे। हम बिहार को टेक्सटाइल का हब बना रहे हैं। ये सारी बातें नए बिहार की ओर इशारा कर रही हैं, जिसका वायदा हमने मतदाताओं से किया था।

सवालः- सदन में सदस्यों की संख्या के लिहाज़ से भाजपा अब नंबर एक हो जाएगी कहा जाता है कि इसके बाद मुख्यमंत्री पद पर उसका दाव बढ़ जाएगा?

जवाबः- चुनाव परिणाम जब आया उसी वक्त हम जेडीयू से सदस्य संख्या में आगे थे लेकिन पार्टी नेतृत्व ने अपने वादे को निभाया क्योंकि 2020 का बिहार चुनाव एनडीए ने नीतीश कुमार के चेहरा पर लड़ा था हम अपने उस वादे पर क़ायम हैं। विध ानसभा में सबसे बड़ी पार्टी हो जाने के बावजूद नीतीश कुमार ही 2025 तक एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री होंगे।❑❑

शेष... लोकतंत्र की ताक़त....

कौन से ख़तरे तथा चुनौतियां हैं जिनका सामना हमें भविष्य में करना पड़ सकता है

कठिन समस्याओं के बीच से लोकतंत्र में बातचीत द्वारा रास्ता निकाल सकते हैं क्योंकि उनके पास पारदर्शिता तथा सम्पूर्ण राजनीति की ताक़त होती है, लोग, विपक्ष तथा सिविल सोसायटी सरकार की सहायता में आ सकते हैं। यद्यपि ऐसा होने के लिए ईमानदारी तथा पारदर्शिता की आवश्यकत है। यह स्पष्ट है कि चीन के साथ इस मुद्दे पर जो जारी है, दुर्भाग्य से ऐसा मामला नहीं है।❑❑

शेष... योगी ने किया...

विभाग।

जसवंत सैनीः संसदीय कार्य तथा औद्योगिक विकास विभाग।

रामकेश निषादः जल शक्ति विभाग।

मनोहर लाल मन्नू कोरीः श्रम एवं सेवायोजन विभाग।

संजय गंगवारः गन्ना विकास एवं चीनी मिलें विभाग।

बृजेश मलिकः वन, पर्यावरण, जन्त उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।

सुरेश शाहीः कारागार।

सोमेन्द्र तोमरः ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग।

अनूप प्रधान वाल्मीकिः राजस्व विभाग।

प्रतिभा शुक्लाः महिला कल्याण, बाल विकास, एवं पुष्टाहार विभाग।

राकेश राठौर गुरुः नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोज़गार एवं ग़रीबी उन्मूलन विभाग।

रजनी तिवारीः उच्च शिक्षा विभाग।

सतीश शर्माः खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग।

दानिश आज़ाद अंसारीः अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक़्फ़ एवं हज।

विजय लक्ष्मी गौतमः ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभिनियंत्रण विभाग।❑❑

शेष... भारतीय बैडमिंटन...

चैम्पियनशिप ट्रॉफी या ओलंपिक स्वर्ण या यहां तक कि एशियाई खेलों का खिताब अपने नाम नहीं करते तो आप एक महान चैम्पियन नहीं हैं। लक्ष्य को एशियाई खेलों के साथ इस साल ऑल इंग्लैंड और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी जगह मिली है।

विश्व चैम्पियनशिप लोह कीन यू, पूर्व चैम्पियन मोमोटा, शीर्ष चीनी शटलर झोउ पेंग, वर्तमान ऑल इंग्लैंड चैम्पियन ली झी जिया और अन्य सभी शीर्ष खिलाड़ियों को हराकर लक्ष्य ने इतने कम आयु में बड़े मंच पर अपने आगमन की घोषणा की है ऐसे में, लक्ष्य के बारे में बताने का यही उपयुक्त समय है।❑❑

एक साल में दिल्ली की हवा में और घुल गया प्रदूषण का जानलेवा ज़हर

राजधानी में एक वर्ष के दौरान पीएम 2.5 का स्तर बढ़ा है। वर्ष 2020 में पीएम 2.5 का सालाना स्तर 84.1 एमजीसीएम (माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर) था, जो 2021 में बढ़कर 96.4 प्रतिशत हो गया। यह दावा हालिया आई रिपोर्ट में हुआ है रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में सबसे प्रदूषित महीना नवंबर रहा। इस माह पीएम 2.5 का स्तर 224. 1 एमजीसीएम दर्ज किया गया। इसके बाद दिसंबर में यह 186.4 एमजीसीएम रहा, जबकि जनवरी में यह 13.7 एमजीसीएम तक दर्ज किया गया। डब्ल्यूएचओ के नए मानकों के अनुरूप पीएम 2.5 का स्तर 5 एमजीसीएम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन राजधानी में पूरे वर्ष किसी भी माह में लोगों को इन मानकों के करीब की भी हवा नहीं मिली। डब्ल्यूएचओ के अनुसार जद पीएम 2.5 का स्तर 35.01 से 50 एमजीसीएम रहता है, तो वह सामान्य से 7 से 10 गुना अधिक है और उसे पर्पल कलर कोड दिया गया है जबकि जब यह 50 एमजीसीएम के स्तर को पार कर जाए तो इसे मरून कलर दिया गया है, जो 10 गुना से भी अधिक है और सबसे अधिक घातक है। लेकिन 2021 में रिकॉर्ड मानसून में दौरान भी राजधानी पर्पल रंग से ऊपर नहीं उठ पाई। सबसे साफ माह सितंबर रहा जब राजधानी में पीएम 2.5 का औसत स्तर 30.2 एमजीसीएम रहा जबकि जुलाई में यह 35.6 प्रतिशत रहा था। अगस्त में इसका स्तर 36.9 प्रतिशत रहा। अन्य महीनों में यह 50 के करीब ही रहा है। मई में इसका स्तर 47.4, जून में 47.1 और अक्तूबर में 73.7 एमजीसीएम रहा है।

दिल्ली के सीएम के आवास पर हमला

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर इस हमले को पंजाब में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री की साजिश के तहत हत्या कराने की नाकाम कोशिश बताई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर भी साथ मिलकर हमला कराने का आरोप लगाया है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि, आम आदमी पार्टी को मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी इस हरकत पर पहुंच चुकी है कि वह केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है, वह केजरीवाल को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ मिलकर बीजेपी के गुंडों ने घर पहुंचकर हमला किया और सीसीटीवी तोड़े गए, बूम बेरियर तोड़े गए। यह एक सोची समझी साजिश के तहत मुख्यमंत्री पर हमला किया गया, अरविंद केजरीवाल को चुनाव में न हरा पाना, पीछे न कर पा रही तो केजरीवाल को खत्म कराना चाहती है। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को हाथ लगाने की कोशिश मत करो। दरअसल बीजेपी युवा मोर्चा के करीब 150-200 कार्यकर्ताओं ने सुबह करीब 11 बजे सीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, ये प्रदर्शन केजरीवाल के द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर विधानसभा में दिए बयान के खिलाफ रखा गया था। हालांकि प्रदर्शन के दौरान करीब 1 बजे कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर सीएम आवास के बाहर तक पहुंच गए। उन्होंने दरवाजे पर पेंट फेंका और यहां लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है, जिनपर कार्यवाही की जा रही है।

शेष.... मंज़र पस-मंज़र

में कच्चे तेल की कीमतों में किसी वजह से गिरावट आती है, तब शायद ही खुले बाज़ार में पेट्रोल या डीजल के दाम में कमी की जाती है। मगर अक्सर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्यों में तेज़ी का हवाला देकर इसकी कीमतों में इज़ाफ़ा कर दिया जाता है। प्रश्न है कि अगर बड़े वाहनों, व्यावसायिक परिसरों, हवाई अड्डों और औद्योगिक इस्तेमाल में खपत के लिए इतनी ऊंची कीमत पर डीजल खरीदा जाएगा, तो क्या इसका असर इनसे संबंधित व्यवसायों पर नहीं पड़ेगा? क्या थोक में महंगे तेल की खरीदारी की भरपाई करने के लिए बड़े वाहन माल ढुलाई या यात्री किराया बढ़ा कर नहीं करेंगे? यह किसी से छिपा नहीं है कि समूचे देश में ज़रूरी वस्तुओं की आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा सड़क परिवहन पर निर्भर है। डीजल की कीमतों में किसी भी इज़ाफे का सीधा असर खुले बाजार में बिकने वाली हर वस्तु पर पड़ता है। ऐसे में डीजल की खुदरा कीमतों में बढ़ोत्तरी नहीं होने का आश्वासन सिर्फ दिलासा भर है।

दरअसल, बीते कुछ समय से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे थे, माना जा रहा था कि इसके पीछे विधानसभा चुनाव बड़ी वजह रहे, जिसमें महंगाई का असर वोटों पर पड़ सकता था। चूंकि अब चुनाव निपट चुके हैं अब हर दूसरे तीसरे दिन पेट्रोल डीजल पर थोडे-थोड़े दाम बढ़ते जा रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि पिछले दो सालों से महामारी पर क़ाबू पाने के लिए लगाई गई पूर्णबंदी आदि वजहों से ज़्यादातर आबादी की आय या तो रुक गई है या फिर ख़त्म हो गई है। करोड़ों लोगों के रोज़गार पर आफत आई है। लोग किसी तरह अपना काम चला रहे हैं। ऐसे में परोक्ष रूप से बढ़ाई गई कीमतें पहले से ही महंगाई के मोर्चे पर जूझ रही आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए नई मुश्किल खड़ी कर रही हैं। सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि वह आम जनता की माली हालत को समझते हुए इस तरह के फैसलों के बजाय अर्थ व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोई वैकल्पिक उपाय करे। जनता पहले से ही बेरोज़गारी और महंगाई की मार झेल रही है, अब अगर और महंगाई बढ़ी तो जनता बेहाल हो जाएगी।

शेष.... प्रथम पृष्ठ

विधि आयोग ने स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका और बैल्जियम के मॉडल पर चुनाव प्रणाली का प्रस्ताव करते हुए कई सिफारिशें की थीं। स्वीडन में केन्द्रीय विधानसभा और नगर निगमों के चुनाव एक साथ प्रत्येक 04 वर्ष के अंतराल में होते हैं। यही स्थिति दक्षिण अफ्रीका में भी है। बेल्जियम में संघीय संसद के चुनाव प्रत्येक 05 वर्ष में यूरोपीय संसद के चुनाव के साथ होते हैं। इसी तरह की प्रणाली स्पेन, हंगरी, पोलैंड, स्लोवेनिया, अल्बानिया, इस्राईल, लेसोथो, फिलीपींस, कोस्टारिका, बोलीविया, ग्वाटेमाला में भी है और पिछले वर्ष इंडोनेशिया ने भी इसी प्रणाली को अपनाया है। हम अमरीकी मॉडल को भी अपना सकते हैं जहां पर राष्ट्रपति और राज्यों के गवर्नरों का चुनाव 04 वर्ष की निर्धारित अवधि के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है और वे अपनी टीम का चयन करते हैं। राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा और सीनेट के प्रति उत्तरदायी होता है किन्तु उन्हें उनका विश्वास मत नहीं लेना होता है। इससे सुशासन, स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित होती है, जिससे वह सत्ता खोने के डर के बिना कठिन निर्णय ले पाता है। समय आ गया है कि भारत में निरंतर चुनाव सिंड्रोम को समाप्त करने के लिए बदलाव किया जाए, यह वक़्त का तक़ाज़ा भी है।❑❑

SHANTI MISSION (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : **27March2022** Posting Days : **MON-TUE.** at **N.D.P.S.O.** New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

•बच्चों को सिखाना होगा 'फेक न्यूज़' को पहचानना

•युद्ध विराम हो लक्ष्य •महँगाई का ईंधन

बच्चों को सिखाना होगा 'फेक न्यूज़' को पहचानना

फ्रांस के स्कूलों में बच्चों को इस बारे में शिक्षित करने के लिए एक बड़ा क़दम उठाया गया है कि कैसे पता लगाया जाए कि कोई वीडियो नकली है या नहीं। यह अपने आप में एक नई पहल है। आज अनेक किशोरों के पास स्मार्टफोन हैं और वे अधिकतर ख़बरें सोशल मीडिया पर ही देखते हैं। वहीं कुछ तक तो केवल विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से ही ख़बरें पहुंचती हैं जिन पर वे उनके मूल स्रोत की जांच किए बिना ही विश्वास भी कर लेते हैं।

कितने ही सोशल मीडिया अकाउंट्स तो वेरिफाइड तक नहीं होते और उनमें से कई तो तरह तरह की फेक न्यूज फैलाने के उद्देश्य से ही बनाए गए होते हैं।

फेक न्यूज का पता लगाने के कई तरीक़े हैं जैसे कि वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर उसे चैक करने के लिए 'गूगल इमेजेज' वेबसाइटों पर अपलोड किया जा सकता है जिससे उसके स्रोत की पुष्टि की हो सकती है। सत्यता की पड़ताल करने के लिए उससे जुड़े विषय के विशेषज्ञों एवे वायरोलॉजिस्ट, डॉक्टर, इतिहासकार आदि से भी सलाह ली जा सकती है स्कूलों को बच्चों के लिए इस संबंध में शिक्षा देने के लिए इंतज़ाम करने चाहिएं।

अमरीका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में करवाया गया एक अध्ययन उस तथ्य की पुष्टि करता है, जिसके बारे में कई शिक्षक पहले से ही जानते हैं कि आज के छात्र स्मार्टफोन से लेकर टैब या लैपटॉप जैसे डिटिजल माध्यमों पर आने वाली सूचनाओं की बाढ़ से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं।

इस मुद्दे पर बहुत दांव पर लगा है। जैसा कि पिछले कुछ सालों में देखा गया है, पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग और फेक न्यूज़ में चुनावों और जनमत संग्रह को प्रभावित करने से लेकर दुखद घटनाओं को जन्म देने की क्षमता है।

उदाहरण '#Pizzagate कांस्पिरेंसी थ्यूरी' का है जिसके ऑनलाइन फैलने के कारण ही अमरीका के वाशिंगटन डी.सी. में स्थित पिज्जा रेस्तरां में एक व्यक्ति ने गोलियां चला दीं। उस व्यक्ति को इस थ्यूरी के चलते यह विश्वास हो गया था कि हिलेरी क्लिंटन वहां बाल तस्करी गिरोह चलाती हैं।

जैसा कि स्टेनफोर्ड शोधकर्ता अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं, 'जिस सहजता से नागरिक मुद्दों के बारे में दुष्प्रचार को फैलने और पनपने दिया जा रहा है, उससे लोकतंत्र को ख़तरा है।' कैलिफोनिया, आयोवा, न्यूयार्क, हवाई, एरिजोना और अन्य अमरीकी राज्यों में विश्व विद्यालयों के छात्रों को इस बारे जागरुक करने की व्यवस्था है परंतु इस संबंध में प्रयास शुरुआती चरण में है कि बच्चों को कम आयु से ही सिखाया जाए कि वे ऑनलाइन दिखने वाली चीज़ों की सत्यता कैसे पता करें। शिक्षक, स्कूल से लेकर गैर लाभकारी संस्थाएं ऐसे पाठ्यक्रम, ऐप्स आदि तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं जो छात्रों को ऑनलाइन सूचना को सही ढंग से समझने में मदद कर सकें।

फ्रांसीसी स्कूलों में दुष्प्रचार के बारे में बच्चों के प्रश्नों का उत्तर दिया और नक़ली को असली से कैसे अलग किया जाए, इस संबंध में सुझावों को आदान-प्रदान किया गया। वास्तव में फ्रांसीसी स्कूलों में बच्चों के लिए इस संबंध में नियमित कक्षाएं लेने की योजना बनाई जा रही है। मिशिगन विश्वविद्यालय भी छात्रों की ख़बरों की वैधता की पड़ताल करने और पूर्वाग्रहों से अवगत होने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए एक कोर्स चला रहा है।

'फेक न्यूज' के विरुद्ध इस तरह की पहल की ज़रूरत केवल अमरीका या फ्रांस को ही नहीं, भारत को भी है। हमें भी अपने स्कूलों में बच्चों के लिए झूठी ख़बरों का पता लगाने के लिए तरीके सिखाने तथा कोर्स चलाने की ज़रूरत है। इस पहल की शुरुआत स्कूलों से करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं और उन्हें सही दिशा दिखा कर ही हम देश का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। ग़ौरतलब हैं कि फेक न्यूज का पता लगाने के कई तरीक़े हैं जैसे कि वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर उसे चैक करने के लिए 'गूगल इमेजेज' वेबसाइटों पर अपलोड किया जा सकता है जिससे उसके स्रोत की पुष्टि की हो सकती है। किसी भी ख़बर की सत्यता की पड़ताल करने के लिए उससे जुड़े विषय के विशेषज्ञों एवे वायरोलॉजिस्ट, डॉक्टर, इतिहासकार आदि से भी सलाह ली जा सकती है स्कूलों को बच्चों के लिए इस संबंध में शिक्षा देने के लिए इंतज़ाम करने चाहिएं।

युद्ध विराम हो लक्ष्य

यूक्रेन पर रूसी हमले के एक माह से अधिक हो जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड में यूक्रेनी शरणार्थियों से मिले, तो दुनिया के ज़्यादातर देशों की भावनाएं उनके साथ थीं। मगर जो राष्ट्रपति बाइडेन ने वहां कहा, उसके बाद उनके समर्थकों के लिए भी उनके रुख़ के साथ खड़े रहना पहले के मुक़ाबले थोड़ा मुश्किल हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी इस यूरोप यात्रा के दौरान न केवल रूसी राष्ट्रपति पुतिन को कसाई बताया, बल्कि भावुकतापूर्ण अंदाज़ में यह भी कहा, 'हे भगवान, यह आदमी सत्ता में बना नहीं रह सकता।' रूसी प्रवक्ता ने बिना देर किए इसका जवाब भी दे दिया। 'अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिका के लोग यह तय नहीं करेंगे कि रूस में कौन सत्ता में बना रह सकता है और कौन नहीं।' अमेरिकी सरकार के लिए भी इस बयान ने असुविधाजनक स्थिति पैदा कर दी थी। अभी बाइडेन अमेरिकी फोर्स वन विमान पर सवार होकर वापसी यात्रा शुरू करते, उससे पहले ही उनके सहायकों की ओर से स्पष्टीकरण आने लगे कि राष्ट्रपति मॉस्को में तत्काल सत्ता परिवर्तन की अपील नहीं कर रहे थे। बहरहाल, बात राष्ट्रपति बाइडेन के मुंह से निकल चुकी है। अब स्पष्टीकरणों के ज़रिए उसे वापस नहीं लिया जा सकता। वैसे, बाइडेन ने यह बात कहकर पुतिन का रुख़ ही मज़बूत किया कि अमेरिका दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखलंदाज़ी करता आया है और कई बार उसने सत्ता परिवर्तन के लिए उन पर हमले भी किए हैं। यूं तो बाइडेन ने जो कहा, युद्ध जैसे हालात में इस तरह की भावनाएं उत्पन्न होना अस्वाभाविक नहीं है। बहुत संभव है कि रूस के भी सत्तारुढ़ हलक़ों में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को लेकर ऐसी ही भावनाएं हों। लेकिन संप्रभुता सम्पन्न देशों के बीच मामले इस तरह की भावनाओं के आधार पर नहीं निपटाएं जाते। ये भावनाएं विवाद को सुलझाने की दृष्टि नहीं देतीं, सिर्फ उस बचकानी ज़िद को जन्म देती हैं जो युद्ध के बेवजह लंबा खिंचते जाने का कारण बनती है। ध्यान रहे, यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूस की यह कथित सैन्य कार्रवाई जब शुरू हुई थी, तब कई विशेषज्ञों को लगता था कि इसके अंजाम तक पहुंचने के लिए दो दिन का वक़्त काफी होगा। मगर एक माह से ज़्यादा हो जाने के बाद स्थिति यह है कि अकल्पनीय नुकसान झेलकर भी यूक्रेन तना हुआ है और रूस को एटमी हथियारों का इस्तेमाल कररने की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ध मकी देनी पड़ रही है। इस बीच, रूस को भी कम नुकसान नहीं हुआ है। सप्लाई लाइन बाधित होने से वहां के भी कई शहरों में ज़रूरी सामानों की किल्लत की ख़बरें आ रही हैं। ज़ाहिर है, युद्ध जितना लंबा खिंचेगा दोनों ओर नुकसान बढ़ते जाएंगे। ऐसे में बेहतर यही होगा कि यह युद्ध रुक जाए। इसकी और कीमत दोनों देशों के आम लोगों को न चुकानी पड़े।

महँगाई का ईंधन

पिछले कुछ समय से रोज़मर्रा की ज़रूरतों के सामान की कीमतें आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। ऐसे में सरकार की कोशिश यह होनी चाहिए थी कि वह लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए ऐसे उपाय निकाले, ताकि आम आबादी के बीच आय और ख़र्च को लेकर संतुलन बना रहे। मगर हालत यह है कि बाजार में अमूमन सभी वस्तुओं की कीमतों में कमी के बजाय इजाफा ही होता जा रहा है। खाने-पीने की चीज़ों तक के दाम लंबे समय से जिस स्तर पर हैं, उससे बहुत सारे लोगों के सामने अलग-अलग स्तर पर मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। इस बीच, डीजल की थोक खरीदारी में एक साथ पच्चीस रुपए प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी का बाजार पर बुरा असर देखने को मिल रहा है, जिसका अंदाज़ा पहले से ही था। यों डीजल के दाम में वृद्धि के पीछे सरकार की दलील यह है कि बढ़ोत्तरी केवल थोक खरीदारी के लिए की गई है और खुदरा बिक्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यह भी बताया जा रहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज़ी आई है। जिसका कारण रूस यूक्रेन युद्ध है। इसकी वजह से बस या माल जैसे व्यावसायिक परिसरों के लिए डीजल की खरीदारी से तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा था। विचित्र यह है कि अगर कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार

यह किसी से छिपा नहीं है कि पिछले दो सालों से महामारी पर क़ाबू पाने के लिए लगाई गई पूर्णबंदी आदि वजहों से ज़्यादातर आबादी की आय या तो रुक गई है या फिर ख़त्म हो गई है। करोड़ों लोगों के रोज़गार पर आफत आई है। लोग किसी तरह अपना काम चला रहे हैं। ऐसे में परोक्ष रूप से बढ़ाई गई कीमतें पहले से ही महंगाई के मोर्चे पर जूझ रही आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए नई मुश्किल खड़ी कर रही हैं।

बाक़ी पेज 11 पर

ज़रूरी ऐलान

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

रक़म भेजने के तरीक़े:-

❶ मनीआर्डर द्वारा ❷ Paytm या PhonePe द्वारा 9811198820 पर SHANTI MISSION

❸ ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण
SBI A/c 10310541455
Branch: Indraprastha Estate
IFS Code: SBIN0001187

ख़रीदारी चन्दा

वार्षिक	Rs.130/-
6 महीने के लिए	Rs.70/-
एक प्रति	Rs.3/-

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
शांति मिशन
1, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23311455

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in —— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक मोहम्मद तैयब ख़ान ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादक:- मोहम्मद सालिम, फोन:- 23311455, 23317729, फैक्स:- 23316173